mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-06 अंक-189 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

सतना
10 जुलाई 2026 शुक्रवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

सतना, रीवा एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

2027 में नीट परीक्षा 6 दिन चलेगी, कम्प्यूटर बेस्ड होगी

● 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ● पेपर लीक विवाद के बाद बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली,एजेंसी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2027 में कम से कम छह दिन चलेगी। यह पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में कराई जाएगी। परीक्षा के लिए देश भर में 1 हजार से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। NEET पेपर लीक विवाद के बाद यह बदलाव किए जा रहे हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) हर साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए NEET आयोजित करता है। अभी तक यह परीक्षा पेन-पेपर मोड में होती रही है। NEET-UG में हर साल

करीब 25 लाख कैंडिडेट्स हिस्सा लेते हैं। PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि परीक्षा की नई योजना अभी तैयार की जा रही है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE की तरह NEET भी अलग-अलग दिनों में आयोजित होगी। इसी परीक्षा के नतीजों के आधार पर डेंटिस्ट्री, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रमों में भी दाखिला दिया जाता है।

एग्जाम मोड में बदलाव की वजह पेपर लीक विवाद... NEET में यह बदलाव 2024 में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के विवाद के बाद सामने आया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि NEET-UG अब पेन-पेपर की बजाय CBT मोड में कराई जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच कई वर्षों से इस बदलाव पर चर्चा चल रही थी, लेकिन परीक्षा सुधारों की प्रक्रिया पेपर लीक

भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया

पीएम मोदी बोलेः ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम भंडार भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा के लिए जरूरी

मेलबर्न,एजेंसी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) समेत कई क्षेत्र में समझौतों की घोषणा की।

मोदी ने कहा- ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम मिलने से भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर भी विकसित करेंगे। कोकोस (कीलिंग) द्वीप पर स्पेस

ट्रैकिंग टर्मिनल बनाया जाएगा, जिससे भारत के गगनयान मिशन को मदद मिलेगी।

पीएम ने कहा- इंडो-पैसिफिक सिर्फ दो महासागरों का मिलन नहीं है, बल्कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देशों की साझा सोच और आकांक्षाओं का भी प्रतीक है।

उन्होंने कहा- सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने संयुक्त घोषणा पर साइन किए हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर के जरिए दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप और रक्षा उद्योगों को जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा- दोनों देश शिप बनाने, उनकी मरम्मत और रखरखाव (मेंटेनेंस) के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे।

भारत में पेंशन की बचत एक पवित्र अमानतः प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स आज 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक एसेट्स मैनेज करते हैं। भारत में पेंशन की बचत को एक पवित्र अमानत माना जाता है। हम इसे सिर्फ कैपिटल नहीं, करोड़ों परिवारों का भरोसा मानते हैं। भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है।

दुनिया अनिश्चितता और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही... मेलबर्न में कारोबारियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस पावर और बिजनेस एम्बिशन के दर्शन एकसाथ हो रहे हैं। आज दुनिया अनिश्चितता, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है।

: ब्रीफ बॉक्स :

भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली बेसल इंसुलिन

डायबिटीज मरीजों को हफ्ते में एक बार ही लगाना होगा इंजेक्शन, कीमत 2611

नई दिल्ली,एजेंसी। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने बुधवार को भारत में Awiqli (इंसुलिन आइकोडेक) लॉन्च की। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की पहली सप्ताह में एक बार दी जाने वाली बेसल इंसुलिन है, जो टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए है।

इसके आने से रोजाना लगने वाले 365 इंसुलिन इंजेक्शन घटकर साल में 52 रह जाएंगे। कंपनी के मुताबिक, Awiqli का उद्देश्य भारत में इंसुलिन शुरू करने में होने वाली देरी को कम करना है।

राममंदिर चढ़ावा चोरी का पैसा शेयर बाजार में लगाया

पुलिस आरोपियों को घर ले गई, तलाशी ली; अखिलेश बोले-

करुणेश पांडेय अनुकल्प मिश्र लवकुश

एसआईटी लीपापोती

अयोध्या,एजेंसी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा को पुलिस गुरुवार सुबह 9 बजे उसके घर लेकर गई। वहां करीब 20 मिनट तक तलाशी ली। घरवालों से भी पूछताछ की। तलाशी में क्या मिला, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अनुकल्प ने पूछताछ में बताया कि मैं और अविनाश शुक्ला चोरी के पैसों को शेयर मार्केट में लगाते थे। लोगों को ब्याज पर देते थे।

टाइपिंग की गलती से गिरफ्तारी अवैध कैसे?

राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल, बड़ी बेंच जा सकता है मामला

इंदौर,एजेंसी। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने संकेत दिए कि वह इस कानूनी सवाल को बड़ी बेंच के पास भेज सकती है कि क्या गिरफ्तारी मेमो में केवल टाइपिंग की गलती (टाइपो) होने से गिरफ्तारी अवैध मानी जा सकती है और आरोपी को जमानत मिल सकती है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करेगी। साथ ही यह भी जांचेगी कि क्या मेघालय हाईकोर्ट ने केवल टाइपिंग की गलती के आधार पर सोनम रघुवंशी को जमानत देकर सही फैसला किया था।

सरकार बोली- टाइपो के आधार पर जमानत देना गलतः मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यह बेहद गंभीर और सुनियोजित हत्या का मामला है। ऐसे मामले में गिरफ्तारी मेमो में एक टाइपिंग की गलती के आधार पर जमानत देना कानून की गलत व्याख्या है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे।

मणिपुर में अब नगा-कुकी संघर्ष, 5 महीने में 25 मौतें

असम राइफल्स निशाना बनी; दो शहीद जवानों को राजकीय समान, शव घर भेजे

इम्फाल,एजेंसी। मणिपुर में मई 2023 से जारी मैतेई-कुकी जातीय हिंसा के बीच एक नया मोर्चा खुल गया है। राज्य में जारी हिंसा अब नगा और कुकी समुदायों के बीच शिफ्ट हो गई है। उखरुल इसका हॉटस्पॉट बन गया है।

इस साल फरवरी से शुरू हुए इस ताजा संघर्ष में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत-म्यांमार सीमा की निगरानी करने वाली असम राइफल्स के काफिले पर सोमवार को हुआ हमला भी

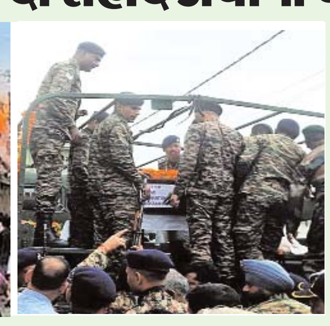

इसी का नतीजा बताया जा रहा है। इस हमले में उत्तराखंड के दो जवान शहीद हो गए थे।

दोनों शहीद जवानों को गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इंफाल एयरपोर्ट पर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव भेज दिया गया। उनका कहना है कि म्यांमार की तरफ से हथियारबंद गुट 'कुकी नेशनल आर्मी (बर्मा)' लगातार सीमा पार कर नगा गांवों पर हमले कर रही है। यह नाराजगी छह अगवा नगा लोगों के क्षत-विक्षत शव 10 जून को मिलने और कामजोंग जिले में नगा गांवों को जलाए जाने के बाद और बढ़ गई।

असम राइफल्स पर कुकी समुदाय के प्रति नरमी का आरोप... दरअसल, नगा का आरोप है कि असम राइफल्स भारत-म्यांमार की 398 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखने में नाकाम रही है। नगा समुदाय के लोग असम राइफल्स पर कुकी समुदाय को लेकर नरमी का आरोप लगाते रहे हैं।

सीएम योगी ने चित्रकूट के प्रमुख संतों के साथ लगाई कामदगिरि पर्वत की पंचकोसी परिक्रमा

चित्रकूट,एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चित्रकूट जनपद प्रवास के दूसरे दिन गुरुवार को प्रभु श्रीराम की तपोभूमि एवं धर्मनगरी चित्रकूट में विधि-विधानपूर्वक पूजन-अर्चन कर भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन किए। पावन कामदगिरि परिक्रमा कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की मंगलकामना की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरहा हनुमान मंदिर से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हुए रघुवर किशोर मंदिर के दर्शन किए तथा श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ भगवान श्री

कामतानाथ की पावन परिक्रमा की। परिक्रमा के दौरान राम मोहल्ला में संत मदन गोपाल दास जी ने पूजन-अर्चन कराया। प्रथम मुखारविंद पर पुजारी भरत शरण दास महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य विधिवत पूजा संपन्न कराई। भरत मिलाप मंदिर में महंत राम मनोहर दास जी ने भगवान भरत के चरण चिन्हों का पूजन एवं आरती कराई। बरहा हनुमान मंदिर में मंदिर के पुजारी विजय तिवारी महाराज द्वारा श्री हनुमान जी का विधिवत पूजन-अर्चन एवं आरती कराई गई।

कामदगिरि महाआरती स्थल पर आचार्य विपिन विराट ने मुख्यमंत्री के करकमलों से भगवान श्री कामतानाथ की महाआरती एवं पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर आचार्य विपिन विराट ने मुख्यमंत्री को कामदगिरि का चित्र एवं रामनामी अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं कामदगिरि क्षेत्र के सभासद अरुण कुमार त्रिपाठी 'जुगल' ने भगवान श्री कामतानाथ का चित्र एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया।

डीआरडीओ को बड़ी कामयाबीः पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण

स्वदेशी रक्षा तकनीक में अहम उपलब्धि हासिल

चांदीपुर,एजेंसी। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार, 8 जुलाई 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण उपयोगकर्ता (भारतीय सेना) द्वारा तय की गई 60 किलोमीटर की न्यूनतम मारक दूरी के लिए किया गया।

'रॉकेट सटीकता के साथ पहुंचने में सक्षम': रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस सफल परीक्षण ने साबित किया कि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट तय लक्ष्य तक सटीकता के साथ पहुंचने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान रॉकेट को सेना में पहले से इस्तेमाल हो रहे पिनाका लॉन्चर से दागा गया। इससे यह भी साबित हुआ कि एक ही लॉन्चर से अलग-अलग दूरी तक मार करने वाले पिनाका रॉकेटों को दागा जा सकता है।

कई डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने मिलकर किया विकासः पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एआरडीई) ने विकसित किया है। इसमें हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (एचईएमआरएल) की प्रमुख भूमिका रही। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (डीआरडीएल) और रिसर्च सेंटर इमारत (आरसीआई) ने भी तकनीकी सहयोग दिया। वहीं, उड़ान परीक्षण का समन्वय इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट (पीएक्सई) ने किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाईः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, भारतीय सेना और इससे जुड़ी उद्योग इकाइयों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि यह लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि इस सफलता से भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी।

डीआरडीओ प्रमुख ने भी की सराहना... रक्षा सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने परीक्षण की पूरी प्रक्रिया पर करीबी नजर रखी। उन्होंने सफल परीक्षण से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी टीमों की सराहना करते हुए उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

देशभर में मानसून का कहर

पुणे-दिल्ली में इमारत ढहीं, 16 लोग दबे, 6 का रेस्क्यू

● खंडाला में लैंडस्लाइड ● सूरत में बाढ़, 3400 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा

भोपाल/ जयपुर/ पटना/ अहमदाबाद/ मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार को भारी बारिश के कारण कचरे का पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर गया, जिससे कचरा प्रबंधन की बिल्डिंग ढह गई। हादसे में 16 लोग मलबे में दब गए थे, जिनमें से छह लोगों को निकाल लिया गया है। मुंबई से बारिश के कारण 9 फ्लाइट डायवर्ट हुई हैं। वहीं दिल्ली के रोहिणी में भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। पुणे के खंडाला में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई, जबकि उसका साथी अब भी लापता है। उधर, गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 19 इंच तक बारिश हुई, जिससे 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया।

जुलाई 1941 में 18 इंच बारिश हुई थीः सूरत में हुई रिकॉर्ड 19 इंच बारिश से तीन दिनों में अलग-अलग

हादसों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 3400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को खाने-पीने की परेशानी झेलनी पड़ रही है।

दिल्ली-जयपुर हाइवे धंसा, गुरुग्राम में 10द्मद्व लंबा जामः भारी बारिश के चलते दिल्ली-जयपुर ह्वा-48 धंस गया है, जिसके कारण 10 किमी लंबा जाम लगा गया। एक स्कूल बस भी नाले में फंस गई। इधर, गुरुग्राम के कई इलाकों में दो-दो फीट पानी भर गया। पुलिस ने कंपनियों से अगले कुछ दिनों तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) देने की अपील की है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार शाम पांच मंजिला इमारत ढह गई। राजस्थान के जालोर में एक जीप नदी में पलट गई। चित्तौड़गढ़ में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई।

महाराष्ट्र में बाढ़ में 3 हजार एलपीजी सिलेंडर बहे

» एमपी में युवक नदी में बहा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी-टिहरी में लैंडस्लाइड, मकान गिरा

भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना, एजेंसी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के बाद 3 हजार LPG सिलेंडर पातालगंगा नदी में बह गए। पनवेल के LPG बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ का पानी घुसने के बाद सिलेंडर बहे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कहीं सिलेंडर मिले तो उसे न छुएं और न ही घर ले जाएं। मध्य प्रदेश में बुधवार को 27 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा दमोह में 1.75 इंच बारिश दर्ज की गई। खरगोन में रूपारेल नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नालूपानी और यमुनोत्री नेशनल हाईवे

पर लैंडस्लाइड हुआ। वहीं, टिहरी में बुधवार को NH-707 पर दुकानों के पास लैंडस्लाइड में एक मकान गिर गया। आसपास के दो से तीन मकान कभी भी गिर सकते हैं।

इधर, राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में बुधवार रात बारिश से एक मकान ढह गया। हादसे में पति-पत्नी समेत तीन लोग मलबे में दब गए। तीनों का रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं, दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है।

उत्तराखंड में भूस्खलन

उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बुधवार को भारी बारिश हुई। उत्तरकाशी में नालूपानी और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। वहीं, टिहरी में बुधवार को NH-707 पर दुकानों के पास लैंडस्लाइड में एक मकान गिर गया।

गुजरात के सूरत में कम से कम 13 लोगों की मौत

गुजरात के सूरत में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बुधवार को कई जगहों पर घरों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानों में घुस गया। सूरत के निचले इलाकों से 3,400 से ज्यादा लोगों को बचाया गया और 3,800 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर भेजा गया।

केरल में 5 लोगों की मौतः केरल के वायनाड में सुरंग सड़क निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या पांच हो गई है। एक शव बरामद किया गया है, चार लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यह भूस्खलन 7 जुलाई को वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ने वाली अनाक्कोम्पोयिल-मेप्पडी सुरंग परियोजना स्थल के पास हुआ।

बढ़ेगी रार या सुलझेगा विवाद? पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ भूपेश बघेल की बड़ी बैठक, चन्नी के फैसले पर सबकी निगाहें

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर जारी असंतोष के बीच अब सबकी नजर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अगले कदम पर टिकी है। पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल लगातार चौथे दिन भी चंडीगढ़ में डटे हुए हैं। शुक्रवार को एक ओर चन्नी अपने समर्थक विधायकों और नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे, वहीं दूसरी ओर बघेल यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों और अन्य नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों तथा संगठनात्मक समन्वय को लेकर बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार चन्नी खेमे की बैठक में इस बात पर मंथन होगा कि आगे पार्टी नेतृत्व से बातचीत किस स्तर पर की जाए। चर्चा इस बात पर भी होगी कि चन्नी सीधे राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगेंगे या फिर चंडीगढ़ में ही भूपेश बघेल के साथ बातचीत कर गतिरोध समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चन्नी समर्थक लगातार चुनाव समिति के गठन और संगठन में हुई नियुक्तियों को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं।

सूची में नहीं होगा फेरबदल: इस बीच कांग्रेस हाईकमान की ओर से चुनाव समिति की सूची में किसी भी प्रकार के फेरबदल की संभावना से साफ इनकार कर दिया गया है। भूपेश बघेल भी लगातार दोहरा चुके हैं कि सूची में कोई बदलाव नहीं होगा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। हाईकमान के इस स्पष्ट रुख के बाद चन्नी खेमे पर संगठनात्मक निर्णय स्वीकार करने का दबाव बढ़ गया है। गुरुवार सुबह भूपेश बघेल ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता तृप्ति राजिंदर सिंह बाजवा से भी मुलाकात की। इससे पहले तीन दिनों में वह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों, एआईसीसी सचिवों, हल्का प्रभारियों, प्रवक्ताओं और विभिन्न नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर चुके हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को एकजुट करना और आपसी मतभेदों को समाप्त करना बताया जा रहा है।

बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की तैयारी

शुक्रवार को यूथ कांग्रेस नेताओं के साथ होने वाली बैठक में युवा कार्यकर्ताओं की भूमिका, चुनावी रणनीति और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो सकते हैं। रवाना होने से पहले वह पंजाब कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, नेताओं से हुई बातचीत और संगठन में चल रहे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे। अब देखना होगा कि चन्नी की बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता निकलता है या पंजाब कांग्रेस का यह सियासी गतिरोध अभी और लंबा खिंचता है।

बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा: 6वें जन्मदिन से पहले स्कूल वैन ने बच्ची को कुचला, मौके पर ही मौत

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके दासनापुरा में बुधवार को एक बेहद दुखद हादसा सामने आया, जहां स्कूल के बाहर खड़ी एक 5 वर्षीय मासूम तनिषा की स्कूल वैन से कुचलकर मौत हो गई। सबसे भावुक बात यह है कि मासूम तनिषा का अगले शुक्रवार को ही छठा जन्मदिन था, लेकिन इससे पहले उसकी मौत पूरा परिवार सदमे में है। दरअसल, तनिषा अपनी मां के साथ 7 वर्षीय बड़ी बहन कनिका को स्कूल से लेने गई थी। इसी दौरान तनिषा अचानक चलती स्कूल वैन के सामने आ गई। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक तनिषा किशोर और मधु की बेटी थी।

पुलिस ने शुरू की जांच: घटना की जानकारी मिलते ही चिक्काबनवारा ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए नेलमंगला सरकारी अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें किसी की लापरवाही थी या नहीं।

अजमेर के किशनगढ़ में बारिश से घर गिरा, तीन लोग मलबे में दबे

अजमेर, एजेंसी। राजस्थान के अजमेर जिले में किशनगढ़ की आजाद नगर हरिजन बस्ती में देर रात भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया। घटना में एक परिवार के तीन सदस्य मलबे में दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मदनगंज पुलिस स्टेशन के एएसआई सत्येंद्र सिंह ने बताया कि रात करीब 2 बजे हमें सूचना मिली कि हरिजन बस्ती में एक घर गिर गया है। यह घर पहाड़ी इलाके में बना हुआ था। टीम मौके पर पहुंची तो मलबे के नीचे तीन लोग दबे हुए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और सरकारी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित परिवार में राहुल, सपना (राहुल की पत्नी), उनका बेटा शामिल हैं। तीनों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने आगे बताया कि घटना की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई उचित समझे जाने पर की जाएगी। प्रशासन ने मकान ढहने की घटना को बारिश से जुड़ी प्राकृतिक घटना बताया है। किशनगढ़ और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों और पुराने मकानों में पानी भरने तथा दीवारें गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

जोधपुर में आईएसआइ हैंडलर के घर एनआईए ने छापा मारा, बैंक के दस्तावेज और बुलेट जब्त

जयपुर, एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) आंध्रप्रदेश की टीम ने बुधवार को राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के हैंडलर जीशान (19) के घर पर छापेमारी की है। एनआईए की टीम सुबह दस बजे जोधपुर के नई सड़क क्षेत्र में स्थित जीशान के घर पहुंची और दोपहर दो बजे तक वहां छानबीन करने के साथ ही परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है। अधिकारियों ने जीशान के बैंक खातों,उसके खर्च, मोबाइल और निरंतर रूप से संबंध रखने वालों के बारे में जांच पड़ताल की है। साथ ही दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जीशान की बुलेट बाइक भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार, जीशान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवाओं का ब्रेनवॉश कर आइएसआइ के लिए काम करने के लिए तैयार करता था। जीशान को 24 मार्च को आंध्रप्रदेश एटीएस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर बुधवार को छापेमारी की गई। जोधपुर सदर बाजार पुलिस थाना अधिकारी मानक राम बिश्नोई ने बताया कि जांच में सामने आया कि जीशान इंटरनेट मीडिया पर 'बेनेक्स' नाम का व्हाट्सएप ग्रुप से वह युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ता था। एटीएस और पुलिस के बाद अब यह मामला एनआइए ने अपने हाथ में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया कि जीशान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। उल्लेखनीय है कि पिछले एक महीने में आइएसआइ के लिए काम करने को लेकर जांच एजेंसियों ने जैसलमेर एवं अलवर से एक-एक युवक को गिरफ्तार किया है।

साइबर फ्रॉड की राशि आने पर पूरा बैंक खाता फ्रीज करना गलत, एसबीआई की निगरानी याचिका खारिज

जोधपुर, एजेंसी। किसी फर्म के खाते में साइबर फ्रॉड की राशि जमा होने पर पूरे खाते को फीज करने की कार्रवाई को राज्य उपभोक्ता आयोग ने गलत मानते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की निगरानी याचिका को खारिज कर दिया। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा एवं सदस्य लियाकत अली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि किसी बैंक खाते में कोई निश्चित राशि विवादित है तो केवल उतनी ही राशि को होल्ड पर रखा जा सकता है। पूरे खाते के लेनदेन पर रोक लगाना उचित नहीं है। मामले के अनुसार, श्रीकार्ट ई-कॉमर्स फर्म के प्रोपराइटर गणपतसिंह एवं जोगाराम का खाता एसबीआई की कृषि उपज मंडी बाड़मेर शाखा में था। वर्ष 2025 में फर्म के खाते में साइबर फाड से संबंधित 1 लाख 5 हजार 898 रुपये की राशि जमा हुई थी। साइबर क्राइम पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर बैंक ने फर्म का पूरा खाता फ्रीज कर दिया था। इसके बाद फर्म की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग बाड़मेर में परिवाद पेश कर खाता डी-फ्रीज करने की मांग की गई।

10वीं पास के लिए आयुर्वेद डॉक्टर बनने का बड़ा मौका, नीट-पीए का नोटिफिकेशन जारी,साढ़े 7 साल का होगा कोर्स

नईदिल्ली, एजेंसी। संस्कृत शिक्षा और आयुर्वेद को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से जनकपुरी स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-प्री आयुर्वेद' (नीट-पीए) की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब संस्कृत या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास विद्यार्थी प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे और आगे चलकर 'बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी' (बीएएमएस) की पढ़ाई कर आयुर्वेद डॉक्टर बन सकेंगे। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा अनुमोदित है और इसे विश्वविद्यालय से संबद्ध देश भर के विभिन्न आयुर्वेद गुरुकुलों के

माध्यम से संचालित किया जाएगा।

गुरुकुल परंपरा से तैयार होंगे श्रेष्ठ चिकित्सक: विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने बताया कि यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के छात्रों में आयुर्वेद के मूल ग्रंथों और संहिताओं को समझने की स्वाभाविक क्षमता होती है। गुरुकुल आधारित इस माडल से आयुर्वेद की शास्त्रीय प्रामाणिकता को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी।

जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होंगे आवेदन

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. पवन कुमार के अनुसार, नीट-पीए के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा। प्रवेश परीक्षा का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में देश भर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा।

पाठ्यक्रम की अवधि और पात्रता नियम: इस समेकित पाठ्यक्रम की कुल अवधि साढ़े सात वर्ष होगी, जिसमें दो वर्ष का प्री-आयुर्वेद गुरुकुलम कार्यक्रम, साढ़े चार वर्ष का बीएएमएस पाठ्यक्रम और एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल होगी।

योग्यता और आयु सीमा: शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी का 10वीं पास होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक होने चाहिए। आयु सीमा: 31 दिसंबर तक अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में किसी भी वर्ग के लिए छूट का प्रावधान नहीं है। नीट-पीए परीक्षा ऑफलाइन (ओएमआर शीट पर) होगी। परीक्षा के लिए 150 मिनट (ढाई घंटे) का समय मिलेगा, जिसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

जबलपुर रेल मंडल में चिकित्सा क्षतिपूर्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा, 10 कर्मचारी निलंबित

जबलपुर, एजेंसी। चिकित्सा क्षतिपूर्ति फर्जीवाड़े में जबलपुर रेल मंडल के सात और कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल 10 कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। विभाग ने रिकवरी की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दावा राशि से अधिक भुगतान का यह खेल आपसी साठगांठ से चल रहा

भत्ता था। हाल ही में जिन सात कर्मियों को निलंबित किया गया है, वह सभी टेक्नीशियन हैं और वर्तमान में भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत पदस्थ हैं। चिकित्सा क्षतिपूर्ति में धांधली का पर्दाफाश न्यू कटनी जंक्शन में पदस्थ कर्मचारी की शिकायत से हुआ। उसके वेतन खाते में अचानक लगभग पांच लाख रुपये आ गए थे। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी वरुण कुमार चतुर्वेदी ने न्यू कटनी जंक्शन के इलेक्ट्रानिक लोको शेड में पदस्थ कुछ अन्य कर्मियों के वेतन-भत्ता रिकार्ड खंगाला तो पता चला कि ऐसे अनियमित भुगतान कुछ अन्य कर्मियों को किए गए हैं। ये किए गए निलंबित-जागेंद्र कुमार श्रीवास, अतुल राजमान लोटन, राजा भैया तिवारी, विनोद कुमार तिवारी, सुरेखा कौरव, अमित कच्ची, बृजेश कुमार पासी। इन पर पहले हो चुकी है कार्रवाईलेखा विभाग के वरिष्ठ लेखा सहायक रामेश्वर अग्रवाल, कार्मिक विभाग के कार्यालय अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव व अतुल कुमार जोहरे।

भारतीय इंजीनियर ने अमेरिका में की पत्नी की हत्या, शव का फोटो भारत में रह रही प्रेमिका को क्यों भेजा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में एक भारतीय इंजीनियर को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पति ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या की और उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस जांच में आरोपी पकड़ा गया। अमेरिका में रह रहे एक 30 वर्षीय भारतीय इंजीनियर को यूएस पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंजीनियर पर नौ माह पहले अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। पुलिस ने बताया कि भारतीय इंजीनियर अविनाश नारने ने अपनी पत्नी रंजीता सब्बीनेनी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने पत्नी के शव की फोटो भारत में रह रही अपनी प्रेमिका को भी भेजी थी। पुलिस जांच के बाद हत्या का मामला साफ हो जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ऐसे रची भारतीय इंजीनियर ने साजिश: 27 अक्टूबर, 2025 को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नारने ने पुलिस को फोन करके बताया कि उनकी पत्नी बाथरूम में बंद हैं और बाहर नहीं आ रही हैं। जब पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, तो उन्हें सबिनेनी जमीन पर पड़ी मिलीं। अधिकारियों ने उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। पूछताछ के दौरान, नारने ने पुलिस को बताया कि वह कुछ काम से अपार्टमेंट से बाहर गए थे। जब वह लगभग 40 मिनट बाद घर लौटे, तो उन्होंने सबिनेनी को बाथरूम में बंद पाया। हालांकि, अधिकारियों को नारने के बाहर रहने के दौरान घर में किसी और के घुसने का कोई सबूत नहीं मिला।

भारत में रहने वाली लड़की से थे प्रेम संबंध: अगले दिन, किंग काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस ने सबिनेनी की मौत को हत्या करार दिया और कहा कि उनकी मौत गला घोंटे जाने के कारण दम घुटने से हुई थी।

यौन उत्पीड़न और मानहानि मामले में ट्रंप को झटका, 1996 में की गई गलती के लिए अब क्यों देंगे 58 लाख डॉलर

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन उत्पीड़न और मानहानि मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को आदेश दिया कि लेखिका ई. जीन कैरोल को वह 58 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि जारी की जाए, जिसे वर्ष 2023 में जूरी के फैसले के बाद एस्क्रो खाते में जमा कराया गया था। ट्रंप के वकीलों ने तुरंत इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन भुगतान पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

2023 में जमा रकम अब कैरोल को मिलेगी: जूरी के 2023 के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने यह राशि एक एस्क्रो खाते में जमा करा दी थी। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद संघीय न्यायाधीश लुईस ए.

कैपलन ने राशि जारी करने का रास्ता साफ कर दिया। शुरुआती 50 लाख डॉलर की क्षतिपूर्ति राशि ब्याज जुड़ने के बाद बढ़कर करीब 58 लाख डॉलर हो गई है। जूरी ने माना था कि ट्रंप ने साल 1996 में मैनहैटन के एक लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर के ट्रायल रूम में लेखिका कैरोल का यौन उत्पीड़न किया था। साल 2019 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में कैरोल द्वारा इस घटना का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किए जाने के बाद ट्रंप ने उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे। उस समय ट्रंप अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में थे। उन्होंने कैरोल के आरोपों को झूठा बताते हुए एक साक्षात्कार में कहा था, 'वह मेरी पसंद की महिला नहीं हैं।'

ट्रंप ने अपने बचाव में दीं ये दलीलें: फैसले के बाद बुधवार को ट्रंप के वकीलों ने कहा कि वे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के राजनीतिक विरोधी न्यायिक व्यवस्था का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रहे हैं।

अपील में उन्होंने दलील दी कि न्यायाधीश कैपलन का आदेश लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से उसके हालिया फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि, बुधवार देर रात द्वितीय अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की न्यायाधीश यूनिस सी. ली ने कैरोल को भुगतान रोकने की ट्रंप की याचिका खारिज कर दी। कैरोल के वकीलों ने अपीलीय अदालत में दाखिल दस्तावेज में कहा, 'अब इस मामले का अंत होना चाहिए।' उन्होंने लिखा, 'कैरोल तीन वर्षों से अधिक समय से जूरी द्वारा तय की गई क्षतिपूर्ति राशि का इंतजार कर रही हैं। उन्हें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए।' इस मुकदमे में ट्रंप स्वयं अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। सुनवाई के दौरान कैरोल ने गवाही दी थी कि डिपार्टमेंट स्टोर में ट्रंप से हुई एक सामान्य और दोस्ताना मुलाकात अचानक हिंसक हो गई थी।

1996 की गलती का अब क्यों हर्जाना दे रहे ट्रंप: वहीं, अब 82 साल की हो चुकीं कैरोल को लेकर ट्रंप लगातार कहते रहे कि वह उन्हें जानते तक नहीं थे। उन्होंने कैरोल पर अपनी किताबों की बिक्री बढ़ाने और राजनीतिक मकसद से आरोप लगाने का भी आरोप लगाया।

डील के लिए गिड़गिड़ा रहा ईरान: ट्रंप ने साझा किया हमले का वीडियो, बोले- 20 गुना ज्यादा ताकत से देंगे जवाब

तेहरान, एजेंसी। मध्य पूर्व में युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका के लगातार हवाई हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव और गहरा गया है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाया तो अमेरिका उससे 20 गुना अधिक ताकत से जवाब देगा।

बुशेहर समेत ईरान के कई शहरों में क्यों हुए धमाके: ईरान के सरकारी मीडिया ने दक्षिणी तटीय इलाकों में कई जगह विस्फोटों की पुष्टि की है। इनमें बुशेहर भी शामिल है, जहां ईरान का प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। इसके अलावा चाबहार, कोनारक, बंदर अब्बास और सीरिक जैसे बंदरगाह शहरों में भी धमाकों की खबर सामने आई है। वहीं,

दक्षिण-पूर्वी शहर इरानशहर स्थित वायुसेना अड्डे पर भी अमेरिकी सेना ने हमला किया।

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने किन देशों पर पलटवार किया: अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए। इससे फारस की खाड़ी में जारी तनाव और बढ़ गया तथा युद्ध समाप्त करने के लिए किए गए अंतरिम समझौते पर भी संकट गहरा गया। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, गुरुवार को ईरान की ओर से किए गए हमले पहले की तुलना में कहीं अधिक बड़े और व्यापक दिखाई दिए। हालांकि, तीनों खाड़ी देशों में किसी बड़े नुकसान की तत्काल पुष्टि नहीं हुई है। कुवैत की सेना ने बताया कि वह लगातार आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा रही है।

ट्रंप ने क्यों कहा कि ईरान समझौते के लिए बेताब है: डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान वॉशिंगटन के साथ युद्धविराम और समझौता करने के लिए बेहद उत्सुक है। उन्होंने यह बयान उस वक्त दिया, जब एक दिन पहले ही वह दोनों देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते को 'खत्म' बता चुके थे। राष्ट्रपति के विशेष विमान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, 'कुछ समय पहले ईरान की ओर से फोन आया था। वे किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वे इसके योग्य हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वे समझौते का पालन करेंगे। हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि फोन पर किससे बातचीत हुई थी। उन्होंने ईरानी नेतृत्व को 'कुछ हद तक पागल' भी बताया।

क्या ट्रंप ने फिर नागरिक ढांचे पर हमले की धमकी दी

ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर बिजली संयंत्रों, समुद्री जल को मीठा बनाने वाले संयंत्रों (समुद्री जल अलवणीकरण संयंत्र) और ईरान के प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र खार्ग द्वीप पर भी हमला कर सकता है। उन्होंने कहा, 'जो भी होगा, बहुत तेजी से होगा।' साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी सेना 'काम पूरी तरह खत्म' भी कर सकती है। तीन तेल टैंकरों पर मंगलवार को हुए हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। उस समय ट्रंप ने कहा था कि उनके लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ अंतरिम समझौता अब समाप्त हो चुका है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत की प्रक्रिया जारी रहने दी जाएगी।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का रुख क्या है

दूसरी ओर, ईरान का कहना है कि अंतरिम समझौते के तहत उसे होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, जो स्थायी शांति समझौते की वार्ता में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि अमेरिका और ईरान के बीच हमलों के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य केवल 'ईरानी व्यवस्था' के तहत ही खोला जाएगा। उन्होंने कहा, 'अमेरिका अब तक यह नहीं समझ पाया कि धमकी और वादाखिलाफी की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप हमला करेंगे, तो जवाबी हमला भी झेलना पड़ेगा।

सेमरिया में खुला उप तहसील कार्यालय, अब 12 पटवारी हल्कों के लोगों को स्थानीय स्तर पर मिलेंगी राजस्व सेवाएं

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के सेमरिया क्षेत्र के लोगों को अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूरस्थ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को सेमरिया में उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया प्रारंभिक रूप से यह कार्यालय सामुदायिक भवन सेमरिया से संचालित किया जाएगा उप तहसील कार्यालय शुरू होने से क्षेत्र के 12 पटवारी हल्कों के किसानों, काश्तकारों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी अब नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख सुधार सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्य स्थानीय स्तर पर ही पूरे हो सकेंगे इससे लोगों के समय, धन और श्रम की बचत होगी। कार्यालय में प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को नायब तहसीलदार उपस्थित रहकर राजस्व प्रकरणों की सुनवाई करेंगी तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों का निपटारा करेंगी प्रशासन का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समय पर और आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं सरकार का उद्देश्य केवल सड़क, भवन और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना नहीं है बल्कि प्रशासनिक सेवाओं को भी आम जनता के नजदीक पहुंचाना है उन्होंने कहा कि उप तहसील कार्यालय की शुरुआत से क्षेत्र के नागरिकों को राजस्व मामलों के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्थानीय स्तर पर सुनवाई होने से प्रकरणों का शीघ्र निराकरण संभव होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शासन की मंशा के अनुरूप संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन की वास्तविक सफलता तभी है जब किसी नागरिक को अपने अधिकार और न्याय के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार नई प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार के माध्यम से सुशासन को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है आने वाले समय में भी जनसुविधाओं का विस्तार जारी रहेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक से अधिक सरकारी सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि उप तहसील कार्यालय से किसानों और ग्रामीणों को राजस्व कार्यों में सुविधा मिलेगी तथा प्रशासन और जनता के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा। कार्यक्रम में सीधी विधायक रीती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन एवं जनसेवा के उद्देश्य के अनुरूप प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेमरिया उप तहसील कार्यालय की स्थापना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है इससे 12 पटवारी हल्कों के किसानों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा अब उन्हें राजस्व कार्यों के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी और स्थानीय स्तर पर ही समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। विधायक ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं को नई दिशा देगी उन्होंने कहा कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति और तेज होगी उप तहसील कार्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व विधायक चुरहट शरदेंदु तिवारी, समाजसेवी देव कुमार सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, जिला पंचायत सदस्य सरस्वती बहेलिया, प्रदीप शुक्ला, सरपंच सुरेश पांडेय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे।

सिंगरौली में कंपनी सिक्योरिटी हेड से मारपीट का विडियो वायरल

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के जमगढ़ी क्षेत्र में एक निजी कंपनी के सिक्योरिटी हेड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सड़क पर उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों और कंपनी अधिकारी के बीच विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर धक्का-मुक्की और हाथापाई की स्थिति बन गई घटना का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार की बताई जा रही है। जमगढ़ी क्षेत्र में निजी कंपनी के सिक्योरिटी हेड अभय श्रीवास्तव अपने वाहन से जा रहे थे इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने सड़क पर वाहनों की आवाजाही से उड़ रही धूल को लेकर वाहन रोक लिया और नियमित पानी का छिड़काव कराने की मांग रखी ग्रामीणों का कहना था कि धूल के कारण आसपास रहने वाले लोगों और आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला बहस से बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गया सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 6 से अधिक ग्रामीण सिक्योरिटी हेड को घेरकर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में कुछ लोगों के बीच धक्का-मुक्की भी दिखाई दे रही है स्थिति बिगड़ने पर सिक्योरिटी हेड किसी तरह वहां से निकलकर अपनी गाड़ी से रवाना हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग आरोप लगाए जा रहे हैं कंपनी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शैलेंद्र कंठ ने बताया कि मामले की जानकारी प्रबंधन को मिल गई है और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की जा रही है।

विवादित इंस्टाग्राम रील पर मचा बवाल, भोजपुरी गाने के बोल को लेकर कानून व्यवस्था पर

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले में सोशल मीडिया पर साझा की गई एक विवादित इंस्टाग्राम रील को लेकर बहस तेज हो गई है रील में एक भोजपुरी गाना इस्तेमाल किया गया है जिसके बोल- 'आज जेल होगी, कल बेल होगी और उसके बाद फिर वही खेल चालू रहेगा को लेकर कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कानून व्यवस्था और पुलिस के प्रति गलत संदेश जाने की आशंका जताई है मामला सामने आने के बाद वीडियो तेजी से वायरल हुआ हालांकि बाद में संबंधित यूजर ने अपनी पोस्ट हटा दी पुलिस ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार यह रील सिंगरौली जिले के कमलेश गुर्जर नामक युवक के इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा की गई थी यह मामला उस समय चर्चा में आया जब बरगवां पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर कथित रूप से अवैध सड़क जाम करने के आरोप में एक हाईवा ट्रक जब्त किया था पुलिस ने नियमानुसार वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने ट्रक को छोड़ने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि न्यायालय के आदेश के बाद ही संबंधित युवक द्वारा यह रील पोस्ट की गई जिसके चलते सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं कई लोगों ने गाने के बोल और रील के संदर्भ को पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था के प्रति चुनौती के रूप में देखा जबकि कुछ लोगों ने ऐसे कंटेंट को समाज के लिए अनुचित बताया। सोशल मीडिया पर यूजर बृजेश शुक्ला ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद इस तरह की रील बनाता है तो इससे कानून और पुलिस का भय समाप्त होने का संदेश जाता है वहीं एक अन्य यूजर अमित कुमार ने लिखा कि इस तरह की प्रवृत्ति भविष्य में अराजकता को बढ़ावा दे सकती है।

धारकुंडी आश्रम मेला परिसर राशि गबन मामले में सचिव पर कार्रवाई की मांग

मीडिया ऑडीटर,सतना (निप्र)। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने वीरपुर पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है उन्होंने आरोप लगाया कि मझगवां जनपद की ग्राम पंचायत वीरपुर में पदस्थ सचिव राकेश रजक द्वारा धारकुंडी आश्रम में मेला परिसर निर्माण के नाम पर जारी राशि में करीब 5 लाख 48 हजार रुपये के गबन का मामला सामने आया है। आशुतोष द्विवेदी ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि धारकुंडी आश्रम क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है ऐसे पवित्र धार्मिक स्थल से जुड़ी विकास राशि में अनियमितता होना लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है उन्होंने प्रशासन से मांग की कि संबंधित सचिव को तत्काल पद से बर्खास्त कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

हनुमानगढ़ में 1.24 करोड़ की लागत से बना उप तहसील कार्यालय भवन शुरू

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के हनुमानगढ़ क्षेत्र के लोगों को अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूरस्थ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को हनुमानगढ़ में 1 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से निर्मित नवीन उप तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। नए उप तहसील कार्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के 34 पटवारी हल्कों के किसानों, काश्तकारों और आम नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी अब नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख सुधार सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकेगा इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होगी तथा उन्हें त्वरित न्याय और प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों और आम नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बना रही है उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के शीघ्र निराकरण से किसानों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

रामपुर नैकिन में 53.10 लाख की लागत से बनेंगे 5 नए आंगनबाड़ी भवन, प्रभारी मंत्री बोले- गांव-गांव तक पहुंच रही पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीधी जिले के रामपुर नैकिन क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुआं में आयोजित कार्यक्रम में 53.10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पांच नवीन आंगनबाड़ी भवनों का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आंगनबाड़ी सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए भवनों के निर्माण से आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी और बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षित तथा गुणवत्तापूर्ण वातावरण उपलब्ध हो सकेगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से कुपोषण की स्थिति में सुधार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाए और भवन निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल बच्चों को पोषण देने का माध्यम नहीं हैं बल्कि यह बच्चों के प्रारंभिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की मजबूत नींव तैयार करने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत सामाजिक आधारभूत संरचना जरूरी है आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है इससे ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं वाले आंगनबाड़ी भवन बनने से बच्चों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा और महिलाओं को भी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी पूर्व विधायक चुरहट शरदेंदु तिवारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण समय की आवश्यकता है उउन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र समाज के भविष्य निर्माण की आधारशिला हैं।

डिसमिल जमीन विवाद में आमने-सामने आए दो पक्ष, सीधी में मारपीट और धमकी के आरोप

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के अमरवाह गांव में महज 2 डिसमिल जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है करीब एक महीने से जारी विवाद में गुरुवार को दोनों पक्षों ने थाना जमोड़ी पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों ने मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और रास्ता रोकने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है जानकारी के अनुसार रिटायर्ड आर्मी अधिकारी शमशेर बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने विवादित जमीन पर जेसीबी मशीन चलाकर उनके घर के पास ठोकर कर दी जिससे मकान में दरारें आ गईं उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने दूसरे पक्ष के कथित अवैध रेत और मुरम कारोबार की शिकायत प्रशासन से की थी जिसके बाद से उनके साथ विवाद बढ़ गया। शमशेर बहादुर सिंह का आरोप है कि उन्हें लगातार गाली-गलौज और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर तक आने-जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है जिससे परिवार को परेशानी हो रही है। वहीं दूसरे पक्ष के राणा प्रताप सिंह ने इन आरोपों को गलत बताते हुए शमशेर बहादुर सिंह और उनके परिवार पर चोरी, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है उनका कहना है कि घर निर्माण के लिए रखी गई लकड़ी और अन्य सामग्री उठा ली गई विरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और लाइसेंसी बंदूक दिखाकर डराने का प्रयास किया गया। दोनों पक्षों ने गुरुवार सुबह थाना जमोड़ी में अलग-अलग आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की पुलिस के अनुसार पिछले एक महीने में दोनों पक्ष कई बार थाने और तहसील स्तर पर शिकायत कर चुके हैं।

रेलवे पर किसान की जमीन कब्जाने का आरोप, जेसीबी से फसल बर्बाद करने का दावा, रेलवे बोला- अधिग्रहित भूमि पर हो रहा निर्माण

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के जमोड़ी गांव में रेलवे और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद सामने आया है एक किसान ने आरोप लगाया है कि बिना पूर्व सूचना और अनुमति के उसकी निजी जमीन पर जेसीबी मशीन चलाकर नाली निर्माण कराया गया, जिससे खेत में खड़ी धान और अरहर की फसल बर्बाद हो गई किसान ने मामले की शिकायत तहसीलदार, एसडीएम और रेलवे अधिकारियों से कर कार्रवाई की मांग की है वहीं रेलवे ने आरोपों को खारिज करते हुए निर्माण कार्य को अपनी अधिग्रहित भूमि पर होना बताया है। जानकारी के अनुसार जमोड़ी गांव निवासी किसान महेश प्रताप सिंह का आरोप है कि गुरुवार सुबह रेलवे और राजस्व विभाग के कर्मचारी जेसीबी मशीन लेकर उनके खेत में पहुंचे और बिना किसी सूचना के खुदाई शुरू कर दी किसान का कहना है कि खेत में धान और अरहर की फसल लगी हुई थी जो जेसीबी चलने के कारण पूरी तरह खराब हो गई। महेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि रेलवे ने पहले अपनी सीमा निर्धारित कर पिलर लगाए थे, लेकिन अब कर्मचारी उन पिलरों से करीब 10 फीट आगे बढ़कर उनकी निजी स्वामित्व वाली जमीन पर नाली निर्माण कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है और अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं दिया गया है किसान ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत तहसीलदार, एसडीएम और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से की लेकिन शुरुआत में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई इसके बाद उन्होंने दोबारा तहसीलदार गोपद बनास राकेश शुक्ला को लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की। महेश प्रताप सिंह का कहना है कि इस कार्रवाई से केवल उनकी ही नहीं बल्कि गांव के सात अन्य किसानों की जमीन और फसल भी प्रभावित हुई है किसानों का आरोप है कि बिना सहमति के खुदाई और निर्माण कार्य किए जाने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है वहीं इस मामले में तहसीलदार राकेश शुक्ला ने बयान देने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर ने संवेदनशील मामले को देखते हुए उन्हें इस संबंध में कोई बयान देने से मना किया है।

भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से अतिथि शिक्षकों में नाराजगी, मऊगंज में आयुक्त के नाम सौंपा ज्ञापन

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों को लेकर जिले के अतिथि शिक्षकों ने चिंता जताई है गुरुवार शाम अतिथि शिक्षक समन्वय समिति, जिला मऊगंज ने लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी के माध्यम से ज्ञापन दिया अतिथि शिक्षकों का कहना है कि नई भर्ती प्रक्रिया और विद्यालयों में पद संरचना में हुए बदलाव के कारण बड़ी संख्या में अनुभवी अतिथि शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के अतिथि शिक्षक पिछले 17 से 18 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग में लगातार सेवाएं दे रहे हैं उन्होंने पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा दी है और कई वर्षों तक बेहतर परीक्षा परिणाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसके बावजूद उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है समिति ने बताया कि नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण, अतिशेष शिक्षकों के समायोजन, नई भर्तियों, पदोन्नति और नई पद संरचना लागू होने के कारण कई स्कूलों में रिक्त पद कम हो गए हैं इसका असर सत्र 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों पर पड़ा है।

सिंगरौली पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 9 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों के बदले कार्यक्षेत्र नवानगर, बरगवां और सरई थानों को मिले नए प्रभारी

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सिंगरौली पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक सियाज के एम द्वारा बुधवार देर रात जारी आदेश के तहत जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में पदस्थ 9 निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी अधिकारियों को अपने नए पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग द्वारा जारी तबादला सूची में जिले के प्रमुख थानों और चौकियों में बदलाव किया गया है इस

फेरबदल के बाद नवानगर, बरगवां, सरई सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नवानगर और बरगवां थाना प्रभारी बदले: जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक अनिल पटेल को नवानगर थाना प्रभारी के पद से हटाकर अब बरगवां थाना प्रभारी बनाया गया है वहीं निरीक्षक राकेश साहू को सरई थाना से स्थानांतरित कर नवानगर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक प्रह्लाद सिंह मरस्कोले को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए सरई थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है जिले के इन प्रमुख थाना क्षेत्रों में नई पदस्थापना को कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

चौकी प्रभारियों में भी बदलाव: निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ उपनिरीक्षक स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं आदेश के अनुसार उपनिरीक्षक नीरज सिंह चौहान को गोमा चौकी से हटाकर निगरी चौकी प्रभारी बनाया गया है वहीं उपनिरीक्षक संदीप नामदेव को सासन चौकी से स्थानांतरित कर बंधौरा चौकी प्रभारी बनाया गया है उपनिरीक्षक गुरुदत्त सिंह को बरका चौकी से हटाकर निवास चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके अलावा उपनिरीक्षक शिवम सिंह को सरई थाना से स्थानांतरित कर गोमा चौकी प्रभारी बनाया गया है उपनिरीक्षक बी.एल. बैसले को बंधौरा चौकी से हटाकर सासन चौकी प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपनिरीक्षक विनय प्रकाश शुक्ला का भी स्थानांतरण किया गया है। उन्हें निगरी चौकी से हटाकर बैढ़न थाना भेजा गया है।

कानून व्यवस्था मजबूत करने की कवायद: पुलिस विभाग के अनुसार जिले में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था लागू करने और कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक बदलाव किया गया है अधिकारियों के अनुभव और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर विभागीय स्तर पर इस तरह के बदलाव किए जाते हैं ताकि पुलिस व्यवस्था में सक्रियता बनी रहे और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें नए अधिकारियों के आने से थाना और चौकी स्तर पर कार्यप्रणाली में और सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।

थानों और चौकियों में जल्द संभालेंगे जिम्मेदारी: तबादला आदेश जारी होने के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए स्थानों पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नए अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिसिंग व्यवस्था को संभालेंगे नवानगर, बरगवां और सरई जैसे थाना क्षेत्र जिले की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं इन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों, यातायात, कानून व्यवस्था और स्थानीय विवादों से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं ऐसे में इन स्थानों पर नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

पुलिस विभाग में लगातार हो रहे प्रशासनिक बदलाव: सिंगरौली जिले में पुलिस विभाग समय-समय पर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करता रहा है विभाग का उद्देश्य है कि पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का अनुभव मिले और जरूरत के अनुसार जिम्मेदारियों का बेहतर वितरण हो सके।

जांच रपट के अर्द्ध सत्य

संपादकीय

राम मंदिर चंदा-चढ़ावा चोरी की कथित जांच कर रहे विशेष जांच दल की 'परम गोपनीय' रपट सार्वजनिक हो गई। रपट पर साफ अक्षरों में लिखा है-'परम गोपनीय।' फिर यह अंतरिम रपट राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासियों के पास कैसे पहुंची? वहां से कई टीवी चैनलों को रपट कैसे मिली? यकीनन यह कानूनन अपराध का मामला है। रपट को उप्र सरकार 'सार्वजनिक' करती या ट्रस्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति देती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 'परम गोपनीय' रपट को चोर दरवाजे से सार्वजनिक किया गया, लिहाजा खुलासा हो गया कि विशेष जांच दल ने शुरुआती जांच में क्या पकड़ा, किन्हें 'काली भेड़' करार दिया गया और यह चोरी-डकैती कांड कैसे अंजाम दिया गया? ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय बंसल और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों से ही राम मंदिर के भीतर के चोरी-डकैती कांड का पटाक्षेप नहीं हुआ है। विशेष जांच दल की सार्वजनिक रपट पर ही कई सवाल हैं। रपट में चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देव, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव आदि का उल्लेख क्यों नहीं है? चंपत राय तो 'प्रमुख खलनायक' के तौर पर सामने आए हैं, क्योंकि उनके हस्तक्षेप से ही, उनके ड्राइवर टिन्नू यादव को, हुंडियों की चाबियां दी गईं! टिन्नू को कोई प्राधिकार ट्रस्ट ने नहीं दिया था, फिर वह एक सक्षम अधिकारी की तरह व्यवहार क्यों करता रहा? हालांकि विशेष जांच दल अभी टिन्नू यादव की और जांच-पड़ताल करेगा। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल के भीतर है। सवाल यह भी है कि ट्रस्ट ने राम मंदिर के व्यवस्थापक रहे गोपाल राव को अचानक बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? चंपत और अनिल पर लगे गंभीर आरोप उन पर नहीं थे। वह भी राम मंदिर की व्यवस्था में आरएसएस के एक प्रमुख चेहरा थे। वह ट्रस्ट की बैठक से पहले अचानक बेंगलुरु गए और संघ के सरकार्यवाह (महासचिव) दत्तात्रेय होसबले से मिले। क्यों मिले, इसका कोई खुलासा नहीं है। विशेष जांच दल ने आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जो कागजात मांगे थे, वे जांच दल को सौंपे गए, लेकिन अंतरिम रपट में घोटालास्पद भूमि-सौदों का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। क्या जांच दल ने मान लिया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने बिल्कुल ईमानदार जमीन-सौदे किए थे? इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने यह तथ्य बेनकाब किया था कि अनिल मिश्रा निर्माण-कार्यों पर 40 फीसदी कमीशन मांगते थे, लिहाजा फर्जी बिल भी बनाए गए। महिपाल सिंह भी राम मंदिर में लेखाधिकारी थे, जिन्होंने चोरी और दूसरी गड़बडियों को लेकर चंपत राय और अनिल मिश्रा को अवगत कराया था। उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। विशेष जांच दल ने इन दोनों के बयान भी दर्ज क्यों नहीं किए? वे चोरी-डकैती के सुराग खोलने में एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो सकते थे। सार्वजनिक रपट में खुलासा है कि बीती 5 जून की छापेमारी में 78.94 लाख रुपए बरामद किए गए थे। यह नकदी बरामदगी 21 दिन तक कृष्ण मोहन के घर एक संदूक में रखी गई। कृष्ण मोहन को अब ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया है।

संत भी प्रेरित होते थे ब्रह्माकुमारीज प्रेम बहन से!

डॉ श्रीगोपाल नारसन

प्रेमलता बहन का यह सौभाग्य रहा कि उन्हें बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान मिलना शुरू हो गया था।वे बचपन से ही ब्रहमाकुमारीज संस्था से जुड़ गई थी। 18 जनवरी 1940 में जन्मी प्रेम लता बहन को सन 1952 में ईश्वरीय ज्ञान मिला और सन 1956 में वे इस ज्ञान के सागर में जीवनभर के लिए समर्पित ही गई। ब्रह्माकुमारी प्रेमलता के अंदर ब्रहमाकुमारीज संस्था के संस्थापकब्रहमा बाबा ने ईश्वर के प्रति मधुर मिलन की ललक देखी, तोउन्होंने उन्हें अपने सानिध्य में ले लिया। ब्रहमा बाबा चाहते थे, कि परमात्मा शिव का ईश्वरीय ज्ञान भक्ति मार्ग के साधु संतों को भी मिले।जिसके लिए उन्होंने ब्रहमाकुमारी प्रेमलता बहन को इस ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनाया और उन्हें हरिद्वार में जाकर साधू संतों को ईश्वरीय ज्ञान बांटने की सेवा दी। निराकार परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य ज्ञान एवं राजयोग शिक्षा को संत समाज व देवभूमि में फैलाने वाली प्रेमलता दीदी जी, न केवल ब्रह्मा कुमारी संगठन को, अपितु समग्र देवभूमि को, एक पिता परमात्मा और एक दिव्य परिवार मानकर वैशिक शांति, एकता, भाईचारा, सहयोग एवं वसुधैव कुटुम्बकम की भावना व आदर्शों को देश विदेश में खूब प्रचारित, प्रसारित और सुदृढ करती रही।प्रेमलता दीदी जी सभी वर्गों के लिए आध्यात्मिक सेवाओं का प्रावधान पूरी दिल से करती थी । हर वर्ष साधु संतों के लिए खास राजयोग शिविर, स्नेह मिलन, संगोष्टियां एवं सम्मेलन आदि कराकर वे सन्तो के बीच बेहद लोकप्रिय रही।उनका मानना था, संत समाज से ही सही जनजागृति, समाज, संस्कृति, प्रकृति, पर्यावरण एवं विश्व कल्याण सम्भव है। मूल्य निष्ठ, साकारात्मक एवं संवेदनशील आध्यात्मिकता मार्ग से ही संभव है।यही मार्ग शक्तिशाली उत्प्रेरक है, जो जन मानस व देश समाज को सही दिशा और दशा प्रदान कर सकता है। उनका कहना था, आध्यात्मिकता ही स्वच्छ, स्वस्थ, संतुलित, समृद्ध और सुखमय जीवन, समाज, संस्कृति व संसार निर्माण का आधार है। नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हेतु वे सदा तत्पर रहती थी।जीवन को स्वस्थ, सुखी, सात्विक, समृद्ध एवं संतुलित बनाने हेतु प्रेमलता दीदी जी संतो को आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग ध्यान, मानवीय मूल्य, सादा, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करती थी। देवभूमि उत्तराखंड में, समय - समय पर और जगह -जगह पर राजयोग मैडिटेशन शिविर लगवाकर वे जन मानस को स्वस्थ, नशामुक्त तथा व्यसन मुक्त रखने का हर संभव प्रयास करती रही। राजयोगिनी बीके प्रेमलता दीदी सन्तो के बीच जाकर पहले उनकी सुनती थी और फिर उन्हें बड़े सम्मान के साथ ईश्वरीय ज्ञान देने लगती।संत समाज के लोग भी प्रेम बहन के रूहानी आभामंडल में खोकर स्वयं को शिष्य समान समझने लगते और लगता जैसे प्रेम बहन हैड मास्टर के रूप में उन्हें धर्म और आध्यात्म का पाठ पढ़ा रही हो,वे कहती थी,आज भी हम परमात्मा शिव को पहचान नही पा रहे है।जबकि यह सच है कि कोई एक चेतन तत्व जिसे हम आत्मा कहते है, वह हमारे शरीर में रहकर शरीर की सभी गतिविधियों को संचालित करता है। हमारी भृकुटि में रहने वाली आत्मा शरीर में जो कुछ भी होता है उससे सदा अप्रभावित रहती है। यह चेतन तत्व रूपी सदा ही इतिहास के परे का सच है। यदि चेतन तत्व यानि आत्मा का कनेक्शन परम तत्व यानि परमात्मा से जुड़ जाए तो यह तत्व संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसे नियंत्रित तो नही कर सकता लेकिन दृष्टा अवश्य बन सकता है। शरीर की मृत्यु पर यही चैतन्यस्वरूप आत्मा वर्तमान शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। जब यह प्रश्न मन मे उठता है कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? इस प्रश्न में मेरा शब्द उस शरीर की ओर संकेत कर रहा है, जो प्रति क्षण बदल रहा है। मेरी मृत्यु के बाद जो कुछ भी होगा, वह उसी शरीर का होगा जिसने मेरे जन्म के समय वह शरीर धारण किया था, जिसे मैं अपना शरीर कहता आया हूं। अगर हम अपने जन्म के पहले से उस तत्व को जान लें तो फिर यह प्रश्न ही नहीं रहता कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा?प्रेम बहन ने जीवनपर्यंत परमात्मा शिव से सकास लेकर दादा लेखराज यानि ब्रह्माबाबा के जीवन से सब कुछ सीखा।

छात्रशक्ति से राष्ट्रशक्ति में परिणीति के 78 वर्ष

अंकित शुक्ल

भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा को केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं अपितु चरित्र निर्माण, समाजोत्थान व राष्ट्र चेतना का आधार माना गया है। हमारे ग्रंथों में वर्णित है-विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात धर्मम् ततः सुखम्।।

इसी महान शिक्षा दृष्टि को आधुनिक भारत के विद्यार्थी जीवन में मूर्त रूप देने का कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया- 'देह तो थी, ध्येय परिषद ने दिया।' यह केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की अनुभूति है जिन्होंने अपने छात्र जीवन को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखा बल्कि राष्ट्र पुनर्निर्माण का संकल्प लेकर स्वयं को समाज के लिए समर्पित किया। 9 जुलाई भारतीय छात्र आंदोलन के इतिहास में केवल एक तिथि भर नहीं अपितु एक ऐसे विचार की आरम्भ तिथि है जिसने विद्यार्थी जीवन को राष्ट्र जीवन के व्यापक संदर्भ से जोड़ने का अद्वितीय कार्य किया। इसी दिन 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विधिवत पंजीकरण हुआ और तब से लेकर आज तक परिषद निरंतर छात्रहित, समाजहित एवं राष्ट्रहित के त्रिवेणी संगम का प्रतीक बनी हुई है। आज जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी 78 वर्षों की गौरवगाथा का उत्सव मना रही है, तब यह केवल एक संगठन की स्थापना की वर्षगांठ नहीं, बल्कि भारत के विद्यार्थी आंदोलन की उस स्वर्णिम यात्रा का उत्सव है जिसने अनगिनत युवाओं को राष्ट्र सेवा का मार्ग दिखाया। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में स्थापित परिषद ने समय-समय पर यह सिद्ध किया है कि विद्यार्थी भविष्य का नागरिक नहीं, बल्कि वर्तमान का राष्ट्र निर्माता है। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राष्ट्र अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। शिक्षा व्यवस्था औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त थी, समाज दिशाहीनता का अनुभव कर रहा था और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने वाला कोई व्यापक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध नहीं था। ऐसे समय कुछ राष्ट्रनिष्ठ युवाओं ने यह अनुभव किया कि यदि भारत का भविष्य उज्ज्वल बनाना है तो विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाना होगा। इसी चिंतन से परिषद का उदय हुआ। परिषद का ध्येय वाक्य 'ज्ञान, शील, एकता' विद्यार्थियों की पहचान तथा उनकी अंतर्निहित सम्भावना का दूरदर्शी तत्व है। उस दौर में विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक मानसिकता की स्थापना करते हुए परिषद ने नारा दिया 'छात्र शक्ति-राष्ट्र शक्ति '; अतः राष्ट्र पुनर्निर्माण के कार्य का प्राथमिक आधार विद्यार्थी शक्ति का एकसूत्र होना है।

इस यात्रा में परिषद की विशेषता यह भी रही कि उसने रचनात्मक आंदोलन के साथ देशकाल-परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्र की विद्यार्थी शक्ति को दिशा देने के लिए वैविध्यपूर्ण गतिविधियों को अपना मूल स्वभाव बनाया। छात्र समस्याओं के समाधान से लेकर शिक्षा सुधार, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास, आपदा राहत, रक्तदान, सेवा बस्तियों में कार्य, महिला स्वावलंबन, पूर्वोत्तर भारत के साथ भावनात्मक एकात्म, सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक विषय परिषद की कार्ययोजना का हिस्सा बने। परिषद का विश्वास रहा कि परिवर्तन विरोध या विवाद से नहीं बल्कि सकारात्मक सृजन से आता है। यही उसका रचनात्मक दृष्टिकोण है। अभाविप की यात्रा केवल परिसरों तक सीमित नहीं रही। जब भी राष्ट्र के सामने संकट आया, परिषद के कार्यकर्ता सबसे आगे दिखाई दिए। कैंपस टू कम्युनिटी के माध्यम से परिसर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को समाज में उनकी भूमिका का बोध कराने के लिये परिषद ने प्रभावी ढंग से कार्य किया। चाहे प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य हों, सामाजिक जागरण के अभियान हों, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास हों अथवा शिक्षा के अधिकार और गुणवत्ता के लिए संघर्ष, हर क्षेत्र में परिषद ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज का विश्वास अर्जित किया।

परिषद की एक विशेष पहचान उसके विविध आयामों व प्रकल्पों से भी बनती है। स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट (एसएफडी) के माध्यम से पर्यावरण और सतत विकास का विमर्श, स्टूडेंट्स फॉर सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों का सहयोग, राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं कला का संरक्षण, खेलो भारत के माध्यम से युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली के आग्रह के साथ पारंपरिक खेलों का संरक्षण व संवर्धन, स्श्वढ्ढरु (StudentsÓ E&perience in Interstate Living) के माध्यम से पूर्वोत्तर और भारत के अन्य स्थानों के बीच आत्मीय संवाद, थिंक इंडिया के माध्यम से अखिल भारतीय महत्व के संस्थानों से नेतृत्व का निर्माण, शोध के माध्यम से भारत आधारित अनुसंधान तथा सविष्कार के माध्यम से नवोन्मेष व उद्यमिता- ये सभी आयाम परिषद के व्यापक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हैं। इन 78 वर्षों में परिषद ने केवल संगठन का विस्तार नहीं किया बल्कि नेतृत्व की ऐसी परंपरा विकसित की जिसने समाज, शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, न्याय, उद्योग, मीडिया और राजनीति सहित अनेक क्षेत्रों को राष्ट्रनिष्ठ नेतृत्व प्रदान किया। परिषद की कार्यपद्धति व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की अवधारणा पर आधारित है। यहाँ कार्यकर्ता केवल कार्यक्रमों का सहभागी नहीं बनता बल्कि सेवा, अनुशासन, संगठन और नेतृत्व के संस्कार प्राप्त करता है। परिषद की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वैचारिक स्पष्टता और संगठनात्मक अनुशासन है।

समय बदलता रहा, परिस्थितियाँ बदलती रहीं लेकिन परिषद का मूल उद्देश्य नहीं बदला इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, विद्यार्थी-केंद्रित गतिविधियाँ और समाज परिवर्तन से राष्ट्र पुनर्निर्माण का लक्ष्य आज भी उसकी प्राथमिकता में है। यही कारण है कि लाखों विद्यार्थी हर वर्ष परिषद से जुड़कर स्वयं को एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य का भागीदार बनाते हैं। आज नई शिक्षा नीति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शिक्षा, स्टार्टअप संस्कृति, अनुसंधान, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। ऐसे समय में परिषद विद्यार्थियों को केवल रोजगार के लिए नहीं बल्कि उत्तरदायी नागरिक और सक्षम नेतृत्व के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही है। शिक्षा को भारतीयता, नैतिकता और आधुनिकता से जोड़ने का जो प्रयास परिषद दशकों से करती रही है, वह आज और भी अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है। अभाविप की अठहत्तर वर्षों की यात्रा अटूट पुरुषार्थ, राष्ट्रभक्ति तथा छात्रशक्ति से राष्ट्रशक्ति की परिणीति की जीवंत कथा है। आज आवश्यकता है कि देश का प्रत्येक विद्यार्थी केवल सफलता का स्वप्न न देखे बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का बोध करते हुए राष्ट्र पुनर्निर्माण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करे।

मुफ्त दवा योजना पर संकट नहीं समाधान की जरूरत

कांतिलाल मांडोत

जीवनरक्षक दवाओं की कमी गरीब मरीजों के लिए गंभीर चुनौती लेकिन समय रहते व्यवस्था सुधारकर सरकार भरोसा फिर मजबूत कर सकती है

राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल केवल एक चिकित्सा संस्थान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लाखों मरीजों की उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र है। हर दिन हजारों मरीज दूर-दराज के गांवों और कस्बों से यहां इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज के साथ सरकार की निशुल्क दवा योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब इलाज के बाद डॉक्टर की लिखी दवाएं अस्पताल के काउंटर पर उपलब्ध नहीं होतीं तो मरीज और उसके परिजनों की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। हाल के दिनों में जीवनरक्षक दवाओं सहित बड़ी संख्या में दवाओं की अनुपलब्धता की खबरें सामने आई हैं। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गरीब और मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहता है। निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदना हर परिवार के लिए आसान नहीं होता। विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए नियमित दवाएं जीवन का आधार होती हैं। यदि ऐसी दवाएं समय पर नहीं मिलें तो बीमारी बढ़ सकती है और आर्थिक बोझ भी कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि निशुल्क दवा योजना को राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में गिना जाता है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिन मरीजों को एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक भेजा गया, कई दिनों बाद आने के लिए कहा गया या फिर बाहर से दवा खरीदने की सलाह दी गई, उनकी परेशानी को सहज रूप से समझा जा सकता है। जो मरीज सैकड़ों किलोमीटर दूर से किराया खर्च करके अस्पताल पहुंचता है, उसके लिए केवल दवा ही नहीं बल्कि दोबारा आने-जाने का खर्च भी बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे मरीजों के सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वह इलाज कराए या परिवार का खर्च चलाए। यह भी सच है कि यह समस्या केवल जयपुर तक सीमित नहीं दिखाई देती। प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में समय-समय पर कुछ दवाओं की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। कहीं सप्लाई में देरी होती है तो कहीं खरीद प्रक्रिया पूरी होने तक मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। इससे सरकार की अच्छी योजनाओं की छवि प्रभावित होती है। जनता यह नहीं देखती कि कमी किस स्तर पर हुई है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अस्पताल पहुंचने पर दवा मिलनी चाहिए। हालांकि इस पूरे विषय को केवल आलोचना के दृष्टिकोण से देखना भी उचित नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने पिछले कई वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं का उल्लेखनीय विस्तार किया है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना जैसी पहल ने लाखों गरीब परिवारों को राहत दी है। यदि ये योजनाएं नहीं होतीं तो गरीब मरीजों का इलाज और भी कठिन हो जाता। इसलिए यह कहना उचित होगा कि योजना में कमी नहीं है बल्कि उसके क्रियान्वयन के कुछ हिस्सों में सुधार की आवश्यकता है। अस्पताल प्रशासन का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि कुछ दवाएं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से उपलब्ध नहीं हो पातीं तो स्थानीय स्तर पर खरीद की जाती है। कई बार आपूर्ति करने वाली कंपनियों की ओर से विलंब होने के कारण अस्थायी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि वास्तव में ऐसा है तो इसका समाधान भी प्रशासनिक स्तर पर संभव है। दवाओं की उपलब्धता का नियमित आकलन, समय रहते नई खरीद प्रक्रिया और वैकल्पिक व्यवस्था से इस प्रकार की कठिनाइयों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां भी उतनी ही अधिक होती हैं। राजस्थान जैसे विशाल राज्य में करोड़ों लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आसान कार्य नहीं है। दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है और कई बार अनुमान से अधिक मरीज आने के कारण स्टॉक जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस समस्या को केवल लापरवाही कह देना भी पूरी तस्वीर नहीं दर्शाता। आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रशासन और दवा आपूर्ति एजेंसियां मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिससे आवश्यक दवाओं का भंडार हमेशा सुरक्षित रहे। तकनीक का बेहतर उपयोग भी इस दिशा में बड़ा समाधान बन सकता है। यदि सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं का ऑनलाइन स्टॉक रियल टाइम अपडेट हो तो यह पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में बची है और कब नई खेप की आवश्यकता होगी। इससे आपूर्ति में होने वाली देरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। मरीजों को भी मोबाइल या हेल्पलाइन के माध्यम से यह जानकारी मिल सके कि संबंधित दवा किस अस्पताल में उपलब्ध है। इससे उन्हें अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही अस्पतालों में मरीजों के साथ संवाद की व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। यदि किसी दवा की अस्थायी कमी है तो मरीज को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि दवा कब तक उपलब्ध होगी या उसका सुरक्षित विकल्प क्या है।

पेट्रोल में एथनाल : आख़िर ये माजरा क्या है?

भारत में इन दिनों पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल का मिश्रण किये जाने यानी ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से होने वाले नुक़्सान को लेकर बहस छिड़ गयी है। इसके प्रयोग से देश भर से वाहनों के इंजन ख़राब होने की ख़बरें मीडिया में आने लगी हैं। ई20 उपभोक्ता अब न केवल इसकी शिकायतें करने लगे हैं बल्कि जगह जगह इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी होने लगे हैं।

निर्मल रानी

गत दिनों तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ई20 मिश्रित पेट्रोल के विरोध में प्रदर्शन किया गया।और इससे वाहनों को होने वाले नुक़्सान को लेकर सरकार को अवगत कराया गया। भारत में हो रहे इसके विरोध व इसके इस्तेमाल से आ रही परेशानियों व वाहनों को हो रहे कथित नुक़्सान की ख़बरों के बीच पड़ोसी देश भूटान ने भी भारतीय तेल कंपनियों से एथनाल मिश्रित ई 20 पेट्रोल वहां न भेजने व केवल पूर्व में भेजा जा रहा केवल शुद्ध ङ्क्क100 जैसे पेट्रोल की आपूर्ति करने को कहा है। भूटान द्वारा इसका कारण यह बताया गया है कि पेट्रोल पंपों पर भण्डारण के पुराने भूमिगत फ़्यूल टैंक में ई 20 पेट्रोल के भण्डारण की वजह से पानी के रिसाव का जोखिम है जिससे एथनाल मिश्रित ईंधन ख़राब हो सकता है। क्योंकि इथेनॉल की प्रवृति नमी को आकर्षित करने वाली होती है और वातावरण से नमी लेने पर ईंधन की गुणवत्ता घट सकती है और इंजन में अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाक़े में स्टोरेज और सप्लाई श्रृंखला को आधुनिक करना भी आवश्यक होगा,

जिसमें तत्काल परिवर्तन करना जोखिमपूर्ण माना गया। भूटान द्वारा अपनी आपत्ति में पहाड़ी रास्तों में वाहन के परफ़ार्मेंस पर भी फ़र्क़ पड़ने का संदेह व्यक्त किया गया है। भारत में भी देश भर से गाड़ियों के ख़राब होने,गाड़ियों की पेट्रोल टंकी के गलने व ज़ंग लगने,माइलेज कम होने व इंजन के ख़राब होने तक की शिकायतें आने लगी हैं। और उधर इसी ई 20 पेट्रोल की आपूर्ति व खपत की आड़ में शुद्ध पेट्रोल यानी एक्सपी100 का मूल्य 167 रूपये प्रति लीटर तक हो गया है। एथनाल के उपयोग से केवल गाड़ियां ही ख़राब नहीं हो रही हैं बल्कि इसके उत्पादन में भी पानी का भी बेतहशा दुरूपयोग किया जा रहा है जिससे भविष्य में यह जलसंकट का कारण भी बन सकता है। ग़ौरतलब है कि एथनॉल का उत्पादन चावल ,मक्का और गन्ना आदि की फ़सलों से होता है। और इन सभी फ़सलों की पैदावार में बेतहाशा पानी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जब इसी फ़सल से एथनॉल बनाया जाता है तो इसमें और भी ज़्यादा पानी ख़र्च होता है। मिसाल के तौर पर चावल से 1 लीटर एथनॉल बनाने में लगभग 10790 लीटर पानी ख़र्च होता है जबकि मक्का से 1 लीटर एथनॉल बनाने में क़रीब 4670 लीटर पानी की खपत होती है इसी तरह गन्ने से मात्र 1 लीटर एथनाल बनाने में तक़रीबन 3630 लीटर पानी लगता है। गोया पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण की नीति देश के जल बचाने के अभियान के ठीक विरुद्ध जलसंकट खड़ा करने में भी सहायक हो सकती है। ज़रा सोचिये कि जब ई20 पेट्रोल की आपूर्ति में जल का इतना इस्तेमाल होता है तो यदि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की इच्छानुसार पेट्रोल में 85 प्रतिशत मिश्रण कर ई85 की आपूर्ति की योजना पर अमल किया गया तो भारत जैसे उस देश में पानी के अकाल को कैसे टाला जा सकेगा जहां के कई इलाक़ों में पहले ही पीने का पानी लोगों को मयस्सर नहीं है? हालांकि अब ख़बर यह भी आ रही है कि भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार अब ई25 पेट्रोल को लागू करने की योजना को फिलहाल टाल सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार अब इस ई25 बदलाव को जल्दबाज़ी में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीक़े से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। देश में पेट्रोल में एथनाल के मिश्रण को लेकर कुछ ज़िम्मेदार लोगों के विरोधाभासी बयान भी सुनाई दे रहे हैं। इसकी वजह से आम लोगों में एथनाल के मिश्रण के प्रति अविश्वास व भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड और एग्ज़ीक्युटिव वाईस प्रेसिडेंट विक्रम गुलाटी ने अपने एक इंटरव्यू में पहले तो यह स्वीकार किया था कि ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से बेशक फ़्यूल एफ़िशिएंसी में कुछ कमी आती है। परन्तु बाद में उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इसे परफ़ॉर्मेंस के मामले में बेहतरीन ईंधन भी बता डाला। इसी तरह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बायोफ़्यूलस के एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग सरावगी ने भी स्वीकार किया था कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ियों की माइलेज में 30 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने गत 30 जून को सर्वोच्च न्यायलय में एक सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया कि ई-20 पेट्रोल का इस्तेमाल फ़िलहाल एक प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। इस बात के सार्वजनिक होने के बाद तो लोगों में और भी आक्रोश फैल गया कि आख़िर प्रयोग के तौर पर उन्हें गिनी पिग अर्थात प्रयोग किये जाने वाला जीव क्यों बनाया जा रहा है। उसके बाद सरकार की तरफ़ से यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि अटॉर्नी जनरल के हवाले से कही जा रही बातें ग़लत हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी एक तरह से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की बातों का समर्थन करते हुए इस बात पर नाराज़गी जताई कि 3.6 करोड़ भारतीय कार मालिकों पर इसतरह के प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं ? उन्होंने कहा कि अभी भारत में 10 में से 9 गाड़ियां ई20 के अनुकूल नहीं हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति आम सहमति के बिना और इसके होने वाले परिणामों को समझे बग़ैर लागू कर दी गई है। खड़गे ने यह भी कहा, हमारी गाड़ियों में इसे ज़बरदस्ती डालने के बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन बदलने की इस प्रक्रिया को प्रयोग नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि जब सरकार का अपना डेटा ही अभी तक तैयार नहीं है, तो नागरिकों को नुक़्सान साबित करने की चुनौती नहीं दी जा सकती। आम लोग गिनी पिग नहीं हैं न ही हमारी सड़कें टेस्ट ट्रैक हैं और देश के उपभोक्ताओं की जेबें सरकार के ट्रायल का बजट नहीं हैं। खड़गे ने ई20 को वापस लेने मांग करते हुये कहा कि सरकार पहले इसे प्रयोग के योग्य,स्वीकार्य व प्रमाणित ईंधन साबित करे, फिर इसे प्रयोग करने की नीति लागू करें। निश्चित रूप से पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रण देश के वाहन धारकों के लिये फ़िलहाल एक समस्या बन गया है और सरकार द्वारा इसके पक्ष में दिए जा रहे तर्कों व विशेषज्ञों व इस नीति के आलोचकों द्वारा उठाये जा रहे बिंदुओं के बीच देश समझ ही नहीं पा रहा है की आख़िर ये माजरा क्या है।

ऑनलाइन स्टोन और बाथ टब मंगाना पड़ा महंगा, 7 लाख की ठगी

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। जिले के माखननगर क्षेत्र में ऑनलाइन निर्माण सामग्री मंगाने के नाम पर करीब 7 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। व्हाइट हाउस निर्माण के लिए स्टोन और बाथ टब सप्लाई करने का झांसा देकर आरोपियों ने पीड़ित से अलग-अलग किश्तों में ऑनलाइन भुगतान करवा लिया लेकिन न तो सामान भेजा और न ही रकम वापस की शिकायत और जांच के बाद पुलिस ने राजस्थान के दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार माखननगर निवासी मुकेश मालवीय ने 22 मार्च 2026 को व्हाइट हाउस निर्माण के लिए एक्सपोर्टर इंडिया वेबसाइट पर स्टोन की तलाश की थी इसी दौरान खुद को नागौरी जेम्स स्टोन का प्रतिनिधि बताने वाले शेरू भाटी ने उनसे संपर्क किया और स्टोन एवं बाथ टब उपलब्ध कराने का भरोसा दिया आरोपी ने विश्वास जीतने के बाद अलग-अलग किश्तों में गूगल पे के माध्यम से करीब 7 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। फरियादी के मुताबिक भुगतान प्राप्त होने के बाद आरोपी ने निर्माण सामग्री वाहन में लोड किए जाने के वीडियो भी व्हाट्सएप पर भेजे जिससे उन्हें भरोसा हो गया कि सामान भेज दिया गया है हालांकि तय समय बीतने के बाद भी सामग्री नहीं पहुंची जब उन्होंने संपर्क किया तो आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा और बाद में अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। अपने साथ ठगी होने का एहसास होने पर मुकेश मालवीय ने 31 मई को माखननगर थाने में शिकायत दर्ज कराई पुलिस ने मामले की जांच की जिसमें प्रथम दृष्ट्या धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर राजस्थान निवासी शेरू भाटी तथा नागौरी जेम्स स्टोन, सीतावत के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की अपील की है अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या कंपनी को बड़ी राशि भेजने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें और केवल सत्यापित माध्यमों से ही भुगतान करें फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है।

सरदार सरोवर समझौते पर सियासत तेज

जीतू पटवारी ने सरकार से पूछा- मध्यप्रदेश के 7,669 करोड़ रुपए के दावे का क्या हुआ?

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े अंतरराज्यीय वित्तीय विवाद के वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति गरमा गई है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि जब मध्यप्रदेश ने परियोजना से हुए नुकसान के आधार पर 7,669 करोड़ रुपए का दावा किया था तो आखिर वह दावा किस आधार पर छोड़ दिया गया उन्होंने सरकार से पूरे समझौते पर श्वेत पत्र जारी करने और विधानसभा में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की। भोपाल स्थित अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल बयान देकर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री जी, आप राजा हरिश्चंद्र नहीं हो कि जो कह देंगे, जनता उसे सच मान लेगी प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि हजारों करोड़ रुपए के दावे का क्या हुआ।

नर्मदा को बताया मध्यप्रदेश की जीवनरेखा: पटवारी ने कहा कि नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवनरेखा है और सरदार सरोवर बांध बनने से सबसे अधिक नुकसान भी मध्यप्रदेश को ही उठाना पड़ा। उनके अनुसार परियोजना के कारण प्रदेश की सबसे अधिक कृषि भूमि, वन क्षेत्र और आदिवासी गांव डूब क्षेत्र में आए हजारों परिवारों के पुनर्वास का सबसे बड़ा दायित्व भी मध्यप्रदेश ने निभाया, जिसके आधार पर राज्य ने 7,669 करोड़ रुपए का दावा प्रस्तुत किया था उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब केवल गुजरात की देनदारी में हुई कथित बचत का प्रचार कर रही है लेकिन यह नहीं बता रही कि मध्यप्रदेश के दावे का क्या हुआ पटवारी का कहना था कि यदि सरकार 1,268 करोड़ रुपए की बचत का दावा कर रही है तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य के हजारों करोड़ रुपए के दावे को क्यों समाप्त किया गया।

सरकार बताए किस आधार पर हुआ फैसला: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सवाल उठाया कि इस समझौते को किस कानूनी और वित्तीय आधार पर मंजूरी दी गई उन्होंने पूछा कि क्या इस विषय पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा हुई क्या विधानसभा को विश्वास में लिया गया और क्या जल संसाधन, पर्यावरण तथा वित्तीय विशेषज्ञों की राय ली गई। पटवारी ने दावा किया कि दिल्ली में हुई बैठक के लिए रवाना होते समय विमान में उनके साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि मध्यप्रदेश अपने वित्तीय दावों को मजबूती से रखने की पूरी तैयारी के साथ बैठक में जा रहा है ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि बैठक के बाद राज्य का दावा पूरी तरह समाप्त कैसे हो गया।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी उठाए सवाल: प्रेस वार्ता के दौरान जीतू पटवारी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पर 5.61 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है और सरकार लगातार नए ऋण लेकर विकास कार्यों की बजाय प्रचार-प्रसार और आयोजनों पर अधिक खर्च कर रही है उन्होंने हाल ही में लिए गए 3,600 करोड़ रुपए के नए कर्ज का भी उल्लेख करते हुए सरकार की वित्तीय नीति पर सवाल उठाए।

झगराखांड में गहराया पेयजल संकट, पार्षदों ने CMO पर लगाए लापरवाही के आरोप, CMO बोले- नियमों से समझौता नहीं होगा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। एमसीबी जिले की नगर पंचायत झगराखांड इन दिनों भीषण पेयजल संकट से जूझ रही है इंटेकवेल की मोटर खराब होने और नगर के कई हैंडपंपों के बंद पड़ जाने से अनेक वार्डों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई है लगातार बढ़ती समस्या के कारण लोगों को पेयजल के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है इस बीच जल संकट को लेकर नगर पंचायत में राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद भी गहरा गया है सत्ता पक्ष के पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) पर लापरवाही और मनमानी कार्यशैली का आरोप लगाया है जबकि सीएमओ ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी नियमों की अनदेखी नहीं की जाएगी पार्षदों का आरोप है कि इंटेकवेल की मोटर खराब होने के बाद समय पर उसकी

मरम्मत या नई मोटर की व्यवस्था नहीं की गई जिसके कारण नगर की जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई उनका कहना है कि कई वार्डों में लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद प्रशासन ने समस्या के समाधान के लिए तत्परता नहीं दिखाई जिससे आम नागरिकों की परेशानी लगातार बढ़ रही है दूसरी ओर नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र पात्रे ने पार्षदों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कुछ जनप्रतिनिधि निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत तत्काल खरीदी कराने का दबाव बना रहे हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्य पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे तथा किसी भी प्रकार के दबाव में नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा सीएमओ ने बताया कि आवश्यक सामग्री और उपकरणों की खरीदी केवल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से ही की जा सकती है। बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाए खरीदी करने पर

ऑडिट के दौरान गंभीर आपत्तियां उठती हैं और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाता है इसलिए सभी कार्य शासन के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों के अनुरूप ही किए जा रहे हैं। फिलहाल नगर पंचायत में पेयजल संकट को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि इस विवाद के बीच सबसे अधिक परेशानी आम नागरिकों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें नियमित पेयजल आपूर्ति का इंतजार है स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आपसी मतभेद भुलाकर जल्द से जल्द मोटर की मरम्मत, बंद हैंडपंपों को चालू कराने तथा वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव: 2027 से 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश में स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 16 जून के स्थान पर 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा शिक्षा विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक अध्ययन अवधि उपलब्ध कराना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना तथा परीक्षाओं की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना सरकार का मानना है कि इससे बोर्ड परीक्षाओं

के परिणामों में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा नई समय-सारिणी के अनुसार 1 अप्रैल से स्कूल खुलते ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी इसी अवधि में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, गणवेश तथा पात्र विद्यार्थियों को साइकिल का वितरण भी किया जाएगा ताकि सत्र के प्रारंभ से ही पढ़ाई बिना किसी व्यवधान के शुरू हो सके। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा छुट्टियों के बाद 16 जून से नियमित शैक्षणिक गतिविधियां पुनः संचालित होंगी। इस प्रकार शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप हो जाएगी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है इससे बच्चे विद्यालयी शिक्षा के लिए अधिक परिपक्व होकर प्रवेश लेंगे और प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की गुणवत्ता बेहतर होगी।

बकरी का शिकार करने खेत में पहुंचा 8 फीट लंबा अजगर, सर्प मित्र ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के नरवर क्षेत्र में शुक्रवार को एक खेत में करीब आठ फीट लंबा अजगर निकल आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया अजगर कथित रूप से एक बकरी का शिकार करने खेत तक पहुंच गया था समय रहते ग्रामीणों की सतर्कता और सर्प मित्र की तत्परता से अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार घटना नरवर स्थित 14 महादेव मंदिर के पीछे बने एक खेत की है। खेत में बंधी बकरी अचानक तेज आवाज में मिमियाने लगी। उसकी आवाज सुनकर मालिक मौके पर पहुंचा तो उसने बकरी के पास एक विशालकाय अजगर को देखा। यह दृश्य देखते ही उसने तुरंत स्थानीय सर्प मित्र सलमान पठान को सूचना दी सूचना मिलते ही सलमान पठान घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया कुछ ही देर में उन्होंने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पूरे रेस्क्यू अभियान को देखा अजगर के आकार को देखकर लोग हैरान रह गए। रेस्क्यू के बाद सलमान पठान ने ग्रामीणों को वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बड़े आकार के अजगर विषैले नहीं होते, लेकिन अपनी मजबूत पकड़ से बड़े जानवरों और इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए ऐसे किसी भी वन्यजीव को देखकर घबराने या स्वयं पकड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

सुरक्षा कारणों से बंद हुआ बरतुंगा-चिरमिरी मुख्य मार्ग, जमीन धंसने और गैस रिसाव की आशंका से बढ़ी चिंता

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। एमसीबी जिले के कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी में सुरक्षा कारणों के चलते एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) के चिरमिरी ओपन कास्ट प्रबंधन ने बरतुंगा-चिरमिरी मुख्य मार्ग को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है यह फैसला ओपन कास्ट खदान क्षेत्र के समीप लगातार बढ़ रहे भू-धंसाव और संभावित गैस रिसाव के खतरे को देखते हुए लिया गया है सड़क बंद होने से बरतुंगा क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय नागरिकों ने सुरक्षित एवं सुगम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार बरतुंगा मुख्य मार्ग से लगे ओपन कास्ट माइंस क्षेत्र में कई स्थानों पर जमीन में गहरी दरारें दिखाई दी हैं लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी और चट्टानों का कटाव बढ़ गया है जिससे सड़क के किनारे की जमीन कमजोर होकर धंसने लगी है स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ स्थानों पर जमीन फटने के साथ गैस निकलने जैसी स्थिति भी देखी गई है हालांकि इस संबंध में तकनीकी जांच की प्रक्रिया जारी है लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। एसईसीएल प्रबंधन का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस मार्ग से वाहनों और आम लोगों का आवागमन सुरक्षित नहीं है किसी भी अप्रिय दुर्घटना से बचने तथा जन-जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सड़क को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है प्रबंधन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि स्थिति सामान्य होने और सुरक्षा मानकों की पुष्टि के बाद ही मार्ग को पुनः खोला जाएगा। सड़क बंद होने से बरतुंगा और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों में नाराजगी देखी जा रही है लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा सुझाया गया वैकल्पिक मार्ग काफी लंबा, समय लेने वाला और असुविधाजनक है इसका सीधा असर रोजाना आने-जाने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और अन्य यात्रियों पर पड़ रहा है।

बस लेकर फरार हुआ पूर्व ड्राइवर, गुरुग्राम में गिरवी रखने का आरोप, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी शहर कोतवाली पुलिस ने एक बस मालिक की शिकायत पर उसके पूर्व ड्राइवर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है आरोप है कि चालक विश्वास में लेकर बस अपने साथ ले गया लेकिन न तो तय शर्तों के अनुसार लोन की किस्तें जमा कीं और न ही वाहन वापस लौटाया शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि आरोपी ने बस को हरियाणा के गुरुग्राम में गिरवी रख दिया ह। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सईसपुरा पीपल वाले कुआं निवासी मुकेश खटीक (33) बस संचालन का व्यवसाय करते हैं उनके नाम पर दो यात्री बसें पंजीकृत हैं। करीब 14 महीने पहले उन्होंने अंबाह निवासी संतोष तिवारी को अपनी बस चालक के रूप में नियुक्त किया था यह बस ग्वालियर-इंदौर मार्ग पर संचालित होती थी। शिकायतकर्ता मुकेश खटीक ने बताया कि बस से अपेक्षित आय नहीं होने के कारण उन्होंने कुछ समय पहले वाहन को शिवपुरी बस स्टैंड पर खड़ा कर दिया था इसी दौरान 10 जनवरी 2026 को चालक संतोष तिवारी ने उनसे बस अपने संचालन में देने का प्रस्ताव रखा उसने भरोसा दिलाया कि वह नियमित रूप से बस का संचालन करेगा और वाहन के लोन की मासिक किस्तों सहित अन्य देनदारियों का समय पर भुगतान करेगा। मुकेश के अनुसार आरोपी की बातों पर विश्वास करते हुए उन्होंने परिचित लोगों की मौजूदगी में बस की चाबी उसे सौंप दी हालांकि इस लेन-देन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कोई लिखित अनुबंध या एग्रीमेंट नहीं किया गया था शिकायतकर्ता का कहना है कि विश्वास के आधार पर बस सौंपना अब उनके लिए भारी पड़ गया आरोप है कि बस अपने कब्जे में लेने के बाद संतोष तिवारी ने न तो वाहन की लोन किस्तें जमा कीं और न ही किसी प्रकार का भुगतान किया। जब भी मुकेश ने उससे बस वापस मांगी वह अलग-अलग बहाने बनाकर टालता रहा जून 2026 में दोनों के बीच अंतिम बार बातचीत हुई थी जिसके बाद से आरोपी का मोबाइल फोन बंद है और वह लगातार संपर्क से बाहर है। मुकेश खटीक ने बताया कि आरोपी से संपर्क नहीं होने पर उन्होंने अपने स्तर पर बस की तलाश शुरू की इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि संतोष तिवारी ने बस को हरियाणा के गुरुग्राम में किसी व्यक्ति के पास गिरवी रख दिया है।

पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को मिल रहा आर्थिक संबल, संतोष कुमार ने जताया सरकार के प्रति आभार

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनकर उभर रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जाती है इस राशि का उपयोग किसान खेती-किसानी से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रहे हैं एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम भल्लौर निवासी किसान संतोष कुमार कुशवाहा ने योजना को किसानों के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि हर चार माह में मिलने वाली 2 हजार रुपये की किस्त खेती के महत्वपूर्ण कार्यों में काफी मददगार साबित होती है उन्होंने बताया कि खाद, बीज, कृषि सामग्री और अन्य जरूरी खर्चों के लिए यह राशि समय पर उपलब्ध हो जाने से खेती करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है संतोष कुमार ने कहा कि पहले कृषि कार्यों के दौरान कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सहायता के कारण आवश्यक कृषि सामग्री समय पर खरीदी जा सकती है इससे खेती के कार्य बिना किसी बड़ी आर्थिक बाधा के पूरे हो रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिल रही है उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग बताते हुए कहा कि यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि उन्नति योजना की भी सराहना की उनका कहना है कि धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

नागद्वारी मेले से पहले आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 750 किलो महुआ लाहन और 53 लीटर अवैध शराब

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नागद्वारी मेले के मद्देनजर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने पचमढ़ी क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया बुधवार को की गई इस कार्रवाई में विभाग ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ लाहन और हाथ भट्टी से निर्मित अवैध शराब जब्त की अभियान के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत आठ प्रकरण दर्ज किए गए प्रशासन का उद्देश्य मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाना है यह कार्रवाई नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी डॉ. राजीव प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में संचालित की गई। नागद्वारी मेले में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पचमढ़ी पहुंचते हैं। ऐसे में मेले के दौरान अवैध शराब की बिक्री और सेवन से किसी प्रकार की दुर्घटना या अप्रिय घटना न हो इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही विशेष अभियान आबकारी विभाग की टीम ने पचमढ़ी क्षेत्र के बड़ा महादेव, हीवर, डीपी पॉइंट, मटकुली, देनवा नदी के किनारे, सिंगानामा और पगारा सहित कई संवेदनशील स्थानों पर एक साथ दबिश दी इन क्षेत्रों में लंबे समय से जंगलों के भीतर हाथ भट्टी से अवैध शराब बनाए जाने और यात्रियों को बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं छापेमारी के दौरान टीम ने कई स्थानों से अवैध शराब निर्माण में उपयोग होने वाला कच्चा माल और तैयार शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान लगभग 750 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 53 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित अवैध मदिरा जब्त की गई। जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 80 हजार 300 रुपये बताया गया है विभाग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल आठ प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आबकारी अधिकारियों ने बताया कि नागद्वारी मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कठिन पहाड़ी मार्ग से होकर यात्रा करते हैं ऐसे में अवैध शराब का सेवन दुर्घटनाओं और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर खतरा पैदा कर सकता है इसी कारण प्रशासन ने मेले से पहले लगातार निगरानी रखने और अवैध शराब के निर्माण, परिवहन तथा बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं आने वाले दिनों में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

नर्मदापुरम में ऑनलाइन ऑर्डर के नाम पर ठगी,स्टोन और बाथ टब भेजने के नाम पर 7 लाख रुपए ऐंठे

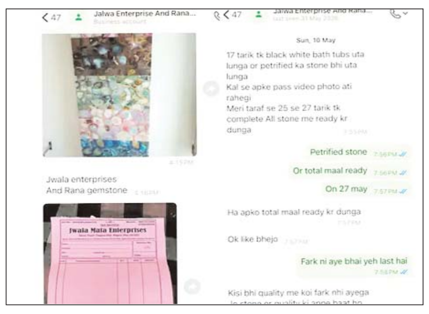

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के माखननगर में व्हाइट हाउस निर्माण के लिए स्टोन और बाथ टब मंगाने के नाम पर 7 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत और जांच के बाद पुलिस ने राजस्थान के दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एक्सपोर्टर इंडिया पर मिला संपर्क, गूगल पे से किए भुगतान: फरियादी मुकेश मालवीय ने बताया कि उन्होंने 22 मार्च 2026 को व्हाइट हाउस निर्माण के लिए एक्सपोर्टर इंडिया वेबसाइट पर स्टोन की तलाश की थी। इसके बाद खुद को नागौरी जेम्स स्टोन का प्रतिनिधि बताने वाले शेरू भाटी ने उनसे संपर्क किया और स्टोन व बाथ टब की सप्लाई का भरोसा दिया। अलग-अलग किश्तों में उन्होंने करीब 7 लाख रुपये गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए।

लोडिंग का वीडियो भेजा, फिर बंद कर लिया मोबाइल: फरियादी के अनुसार, भुगतान के बाद आरोपी ने सामान वाहन में लोड करने के वीडियो भी भेजे। लेकिन तय समय पर सामान नहीं पहुंचा। पूछताछ करने पर आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा और बाद में अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया। इसके बाद पीड़ित ने 31 मई को माखननगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

जांच के बाद दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस: करीब सवा महीने की जांच के बाद पुलिस ने बुधवार देर रात राजस्थान के शेरू भाटी और नागौरी जेम्स स्टोन, सीतावत के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

11 एवं 18 जुलाई को आयोजित होगी विशेष ई लोक अदालत एवं चेक बाउंस प्रकरण लोक अदालत

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री संजीव कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार सीहोर जिला न्यायालय सहित आष्टा, भैरूंदा, बुधनी और इछावर के तहसील न्यायालयों में 11 जुलाई को विशेष ई-लोक अदालत तथा 18 जुलाई को धारा 138 एन. आई. एक्ट अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरणो के लिये विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रो में रहने वाले पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 11 जुलाई को सीहोर में विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्री-लिटिगेशन एवं लंबित समस्त प्रकरणों को शामिल किया गया है। इसमें पक्षकारों की प्रीसिटिंग तथा प्रकरण के निराकरण आदि में यथा संभव वीडियो कान्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार 18 जुलाई को धारा 138 एन.आई.एक्ट चेक बाउंस के लंबित प्रकरणो की बड़ी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारो को त्वरित निराकरण से लाभांवित करने के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धारा 138 एन.आई.एक्ट के अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

कोटवार बनेंगे आपदा सुरक्षा के प्रहरी, शमशाबाद में आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण आयोजित

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार एवं जिला होमगार्ड सेनानी श्री मयंक कुमार जैन के मार्गदर्शन में बुधवार को तहसील कार्यालय शमशाबाद में कोटवारों के लिए आपदा प्रबंधन विषयक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम स्तर पर कार्यरत कोटवारों को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं आकस्मिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना तथा उन्हें ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित बचाव एवं राहत कार्यों, सर्पदंश होने पर तत्काल किए जाने वाले प्राथमिक उपचार, अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय, आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों तथा फर्स्ट एड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से दीं। प्रशिक्षण में बताया गया कि आपदा के समय घबराने के बजाय सही जानकारी और त्वरित कार्रवाई से जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कोटवारों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने ग्रामों में पहुंचकर ग्रामीणों को आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करें। साथ ही स्थानीय स्तर पर जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर लोगों को समय रहते सतर्क करने तथा किसी भी आपदा की सूचना तत्काल प्रशासन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। प्रशिक्षण में विदिशा से पहुंची एसडीआरएफ टीम ने व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी भी साझा की। टीम के प्रभारी एएसआई लक्ष्मी विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैनिक संदीप, श्री देवेंद्र कटोरिया श्री संजय ने विभिन्न आपदाओं के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा तकनीकों, बचाव के तरीकों और प्राथमिक उपचार की जानकारी देकर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

रतलाम पुलिस ने 15 गुम मोबाइल खोजकर लौटाए

2 लाख से अधिक कीमत के फोन हुए बरामद,थाने बुलाकर मालिकों को सौंपे

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम के थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने गुम हुए 15 मोबाइल फोन तलाश कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत 2 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। लंबे समय बाद अपने मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई और पुलिस का आभार व्यक्त किया।

CEIR पोर्टल की मदद से मिली सफलता: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में जिले में गुम एवं चोरी हुमोबाइल फोन की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने भारत सरका के दूरसंचार विभाग के CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के माध्यम से दर्ज शिकायतों का तकनीकी विश्लेषण कर 15 गुम मोबाइल फोन बरामद किए।

तकनीकी जांच से अलग-अलग स्थानों से मिले मोबाइल: थाना प्रभारी गायत्री सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिकायतों के आधार पर मोबाइल फोन की लोकेशन और अन्य तकनीकी जानकारियों का विश्लेषण किया। लगातार प्रयासों के बाद विभिन्न स्थानों से सभी मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को बुधवार शाम थाने बुलाकर सौंप दिए गए।

क्या है CEIR पोर्टल: CEIR पोर्टल गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने और उनकी तलाश में मदद करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद मोबाइल के IMEI नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है। यदि गुम मोबाइल में कोई दूसरा सिम इस्तेमाल किया जाता है तो तकनीकी जानकारी के आधार पर उसकी ट्रैकिंग में पुलिस को मदद मिलती है।

मोबाइल गुम या चोरी होने पर क्या करें: मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें।

CEIR पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर IMEI नंबर ब्लॉक कराएं।

अपने मोबाइल का IMEI नंबर पहले से सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रैकिंग और ब्लॉकिंग की प्रक्रिया आसानी से हो सके। रतलाम पुलिस की इस कार्रवाई से 15 लोगों को अपने गुम मोबाइल वापस मिल सके। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर बिना देरी किए शिकायत दर्ज कराएं और CEIR पोर्टल का उपयोग करें, ताकि मोबाइल की बरामदगी की संभावना बढ़ सके।

खंडवा में स्कूल बस में ओवरलोडिंग,52 सीटर बस में 98 छात्र

दो बसों के टेंडर के बावजूद सिर्फ एक बस का संचालन

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल प्लांट की शिवरिया टाउनशिप में स्कूली बच्चों के परिवहन को लेकर गंभीर मामला सामने आया है।

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाली 52 सीटर बस में 98 बच्चों को बैठाकर ले जाया जा रहा है। दो बसों का टेंडर होने के बावजूद फिलहाल केवल एक बस ही संचालित की जा रही है।

दो बसों का टेंडर, लेकिन सड़क पर सिर्फ एक बस: शिवरिया टाउनशिप में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को मूंदी के निजी स्कूलों तक लाने-ले जाने की जिम्मेदारी थर्मल प्लांट प्रशासन की है।

टेंडर के अनुसार बच्चों की सुविधा के लिए दो बसें संचालित की जानी हैं, लेकिन वर्तमान में केवल एक 52 सीटर बस ही चल रही है।

अधिक भीड़ के कारण कई बच्चे बस के गेट के पास खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं।

सिक्योरिटी विंग ने भी की शिकायत: थर्मल प्लांट प्रशासन ने दो बसों के संचालन का ठेका पंछीराज ट्रैवल्स को दिया है। यही कंपनी कर्मचारियों के लिए भी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है।

बताया गया कि पिछले दो वर्षों से दो स्कूल बसें संचालित हो रही थीं, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र में दूसरी बस उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में टाउनशिप की सिक्योरिटी विंग भी प्रबंधन से शिकायत कर चुकी है।

दो-चार दिन में दूसरी बस आने का दावा: संत सिंगाजी थर्मल प्लांट के कार्यपालन यंत्री (वर्कशॉप) राजेंद्र लखारे ने बताया कि इस वर्ष टेंडर का नवीनीकरण हुआ है।

दूसरी बस सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार की जा रही है और दो-चार दिनों में संचालन शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक ही बस से बच्चों का परिवहन किया जा रहा है।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये पॉलीटेक्निक रायसेन में कॉलेज लेवल काउंसिलिंग प्रारंभ

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, रायसेन में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न रोजगारोन्मुखी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉलेज लेवल काउंसिलिंग 4 जुलाई से शुरू है। द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग पूर्ण होने के बाद इच्छुक विद्यार्थी कॉलेज लेवल काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। महाविद्यालय में दसवीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में , इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश दिए जाएंगे। इच्छुक विद्यार्थी 14 अगस्त 2026 सायं 6:30 बजे तक घर बैठे डीटीई की वेबसाइट https//dte.mponline.gov.in अथवा महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी पसंद के पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के उपरांत विद्यार्थी 4 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों सहित महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रातः 10:30 बजे से सायं 06 बजे तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं। इसके साथ ही दसवीं के साथ आईटीआई अथवा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए उपरोक्त पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश की सुविधा भी उपलब्ध है।

छतरपुर में सूने मकान पर चोरों का धावा

5 लाख की चोरी,नकदी, जेवर और बाइक ले गए, गेहूं-दाल भी नहीं छोड़ी

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 5 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोर घर का ताला तोड़कर नकदी, सोने-चांदी के जेवर, मोटरसाइकिल और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं, घर में रखा गेहूं और दाल भी अपने साथ ले गए। यह घटना सौरा रोड स्थित मित्तल कॉलेज के पास की है। मकान मालकिन चंदा अहिरवार अपने पति बबलू अहिरवार के साथ दौनी गांव गई हुई थीं। वहीं, मकान में रहने वाला किरायेदार तारिक भी मुंबई गया हुआ था, जिससे पूरा मकान खाली था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के अनुसार, चोर एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (MP 16 ZC 4905), करीब एक तोला सोने की चेन, 250 ग्राम चांदी की पायल और बिछिया, गाड़ी की किस्त जमा करने के लिए रखे 2 लाख रुपये नकद तथा अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। चोरों ने घर में रखा गेहूं और दाल भी नहीं छोड़ा।

पड़ोसियों ने दी सूचना: पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो तुरंत चंदा अहिरवार को सूचना दी। परिवार के घर पहुंचने पर अंदर का सामान बिखरा मिला, जिसके बाद चोरी का पता चला। पीड़िता ने करीब 5 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया है।

पुलिस जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 और कंट्रोल रूम के माध्यम से सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, चोरी की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, जबकि अन्य आरोपियों और चोरी गए सामान की तलाश जारी है।

सागर में 72 घंटे बारिश के आसार, तापमान में गिरावट

सीजन में 8.8 इंच वर्षा दर्ज, पिछले साल से अब भी 5.8 इंच बारिश कम

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर में मानसूनी सीजन शुरू होने के बाद से ही तेज बारिश का इंतजार बना हुआ है। पिछले तीन दिनों से आसामान में बादल छा रहे हैं। बादलों के बीच कहीं रिमझिम तो कभी हल्की बारिश हो रही है। बारिश से दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। गुरुवार सुबह से आसमान में बादल छाए हैं। रुक-रुककर हल्की बारिश हुई। इस समय अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम पारा 23 डिग्री सेल्सयस के आसपास बना हुआ है। बारिश के इस सीजन में जिले में 1 जून से अब तक 223 मिमी यानी 8.8 इंच औसत बारिश हो चुकी है। जबकि पिछले साल 9 जुलाई तक जिले में 370.9 मिमी (14.6) इंच बारिश हुई थी।

इस प्रकार जिले में सीजन के 39 दिनों में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जिले में 5.8 इंच औसत बारिश कम हुई है।

जैसीनगर, देवरी, शाहगढ़ में आधा इंच बारिश: पिछले 24 घंटों में जिले के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई। इस दौरान शाहगढ़, जैसीनगर और देवरी में करीब आधा-आधा इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा राहतगढ़, रहली, गढ़ाकोटा, सागर समेत अन्य स्थानों पर पानी गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 72 घंटे तक जिले में मानसूनी गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है।

स्वयं पोर्टल के कोर्स से विद्यार्थियों को मिलेंगे 40% तक क्रेडिट पॉइंट

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी ने कहा है कि जुलाई 2026 सेमेस्टर से स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर शुरू होने वाले MOOC कोर्स को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। यूजीसी का मानना है कि इससे दूरदराज के विद्यार्थियों को भी देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही यह शिक्षा को सस्ती और सुलभ भी बनाएगा। आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और यूजीसी के क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान अपने किसी भी डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम में 40 प्रतिशत तक क्रेडिट पॉइंट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से दे सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई छात्र 4 साल की डिग्री कर रहा है तो उसके 160 क्रेडिट में से 64 क्रेडिट पॉइंट तक वह SWAYAM के कोर्स करके पूरा कर सकता है। क्यों जरूरी है स्वयं पोर्टल से ऑनलाइन पढ़ाई स्वयं पोर्टल (एसडब्ल्यूवायएएम-स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) भारत सरकार का राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच है। इस पर आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के फैकल्टी पढ़ाते हैं। कोरोना के बाद से स्वयं जैसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला है। क्या है यूजीसी पत्र में यूजीसी ने शैक्षणिक संस्थानों को स्वयं पर जुलाई 2026 सेमेस्टर में आने वाले कोर्सों की सूची अनुसार पाठ्यक्रम का चयनकरने के निर्देश दिए है।

मंदसौर में बदला मौसम, झमाझम बारिश हुई,अब तक 7.43 इंच बारिश दर्ज, 9 से 11 जुलाई तक मध्यम बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर में बुधवार को दिनभर तेज धूप और उमस से लोग परेशान रहे, लेकिन शाम होते ही मौसम ने करवट ली और जिलेभर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। मानसून की सक्रियता से किसानों ने भी खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां तेज कर दी हैं।

सुबह से तेज धूप और उमस बनी रही। शाम को अचानक घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में शहर की सड़कों पर पानी भर गया। लोगों ने बारिश का आनंद लिया, जबकि बच्चों ने भी भीगकर मौसम का लुत्फ उठाया।

जिलेभर में कई जगह हुई तेज बारिश: जिला मुख्यालय के अलावा मल्हारगढ़, सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ़, पिपलिया मंडी, नाहरगढ़, दलौदा, अफजलपुर, नारायणगढ़, संजीत, सुंठोद और बरखेड़ा सहित कई क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश हुई। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हुई बारिश से वातावरण में ठंडक घुल गई।

मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जुलाई के बीच जिले में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

वहीं 12 से 14 जुलाई के दौरान बादलों और धूप के बीच मौसम बना रहेगा तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जिले में इस मानसून सीजन में अब तक 7.43 इंच बारिश दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब एक इंच कम है।

गरज-चमक और तेज हवा का येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

विभाग के अनुसार गरज-चमक, आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। लोगों को खराब मौसम में खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

बारिश से खेतों में नमी बढ़ने के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई तेज कर दी है।

जिन क्षेत्रों में पर्याप्त नमी बन चुकी है, वहां बुवाई भी शुरू हो गई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी दिनों में नियमित बारिश होती रही तो इस वर्ष खरीफ उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है।

मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

अभिषेक शर्मा की तस्वीर से छेड़छाड़!

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की तस्वीर और पहचान के कथित अनधिकृत इस्तेमाल से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणियां की हैं। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि डिजिटल दौर में पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) और मानहानि के मामलों के बीच एक बेहद पतली रेखा होती है और कई बार दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अभिषेक शर्मा ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि उनकी तस्वीर, नाम और पहचान का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया। याचिका में यह भी दावा किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी तस्वीर में बदलाव कर भ्रामक सामग्री तैयार की गई।

एआई से तस्वीर बदलने का आरोप

सुनवाई के दौरान अभिषेक शर्मा की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि मूल तस्वीर में क्रिकेटर अपने मैनेजर के साथ थे, लेकिन एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उसकी शक्ल और संदर्भ बदल दिया गया। उनका कहना था कि यह सिर्फ सामान्य फोटो प्रकाशित करने का मामला नहीं, बल्कि एआई के जरिए छेड़छाड़ कर क्रिकेटर की छवि का अनधिकृत इस्तेमाल किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बदली गई तस्वीर लोगों के बीच गलत संदेश देती है और उनके व्यक्तित्व का बिना अनुमति व्यावसायिक एवं डिजिटल इस्तेमाल करती है।

कोर्ट की अहम टिप्पणी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा, 'हम रोज ऐसे मामले देखते हैं, जहां मानहानि और पर्सनैलिटी राइट्स के बीच बेहद पतली रेखा होती है। यह क्षेत्र अभी विकसित हो रहा है। दोनों के बीच कुछ हद तक ओवरलैप भी है। कई बार मानहानि से जुड़ी सामग्री में पर्सनैलिटी राइट्स का पहलू भी शामिल हो सकता है।'

मेटा ने क्या दलील दी?

मेटा की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि जिन आठ वेब लिंक पर फिलहाल सुनवाई हो रही है, उनमें से दो अब उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक अन्य लिंक महज 'पापाराजी शैली की पोस्ट' प्रतीत होती है और पहली नजर में इसे पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। मेटा की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि यदि हर नकारात्मक ऑनलाइन सामग्री को पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन माना जाएगा, तो मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) कंपनियों के लिए इंटरनेट से ऐसे सभी कंटेंट हटाना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन हो जाएगा।

एआई और डीपफेक के बढ़ते मामलों पर चिंता

अभिषेक शर्मा का मामला उन कई मामलों में शामिल है, जिनमें अभिनेता, खिलाड़ी और अन्य सार्वजनिक हस्तियां अपनी तस्वीर, नाम और पहचान के एआई आधारित दुरुपयोग के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा रही हैं।एआई और डीपफेक तकनीक के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने ऐसी चुनौतियां पैदा की हैं, जिनमें किसी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो को बदलकर उसे झूठे घटनाक्रम, उत्पाद या कथाओं से जोड़ दिया जाता है।

चित्रा के. सोमन: कड़ी मेहनत से बनाई पहचान

कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, ग्रांड प्रिक्स में भी लहराया परचम

नई दिल्ली ,एजेसीं। कुछ खिलाड़ियों में टैलेंट कूट-कूटकर भरा होता है, तो कुछ खिलाड़ी कड़ी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसी ही खिलाड़ी रहीं चित्रा.के.सोमन, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर 400 मीटर की दौड़ में देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। चित्रा का जन्म 10 जुलाई, 1983 को केरल के कोट्टायम में हुआ। चित्रा को शुरुआत से ही दौड़ने का काफी शौक था। वह स्कूल स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थीं। जल्द ही उनकी काबिलियत को कोच ने पहचाना और चित्रा ने बतौर धावक करियर बनाने का फैसला कर लिया। साधारण परिवार में जन्मीं चित्रा ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। साल 2004 में हुए एथेंस ओलंपिक में 4×400 मीटर रिले स्पर्धा में चित्रा ने हिस्सा लिया और वह सातवें स्थान पर रहीं। टीम स्पर्धा में उन्होंने मंजीत कौर, के.एम.बीनामोल और राजविंदर कौर के साथ मिलकर 4×400 मीटर रिले में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। टीम की साथी खिलाड़ियों संग मिलकर उन्होंने यह रिले 3:26.89 मिनट में पूरी की। इस प्रदर्शन ने विश्व स्तर पर उनको पहचान दिलाने का काम किया। साल 2006 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में चित्रा का प्रदर्शन लाजवाब रहा और वह सिल्वर मेडल जीतने वाली रिले टीम का हिस्सा रहीं। इसके बाद, साल 2007 में हुई एशियाई ग्रांड प्रिक्स में भी चित्रा का जलवा देखने को मिला। उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 400 मीटर की दौड़ को चित्रा ने 51.30 सेकंड में पूरा किया, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। साल 2007 में चित्रा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय सरकार द्वारा 'अर्जुन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। चित्रा ने उस दौर में इस खेल में अपनी पहचान बनाई, जब काफी सीमित साधन हुआ करते थे।

चौथे टी20 में जीत के लिए टीम इंडिया को सुधारनी होंगी ये 3 गलतियां

बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल पड़ रहा भारी

नई दिल्ली,एजेसीं। पांच मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही भारतीय टीम गुरुवार को चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाना है। भारतीय टीम को अगर सीरीज में पहली जीत दर्ज करनी है, तो अपनी तीन गलतियों को सुधारना होगा। बल्लेबाजी क्रम में फेरबदलः भारतीय टीम को बल्लेबाजी क्रम में लगातार फेरबदल करना काफी महंगा पड़ा है। तीसरे टी20 में भी तिलक वर्मा से ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया था, जबकि शिवम दुबे से पहले बैटिंग करने हर्षित राणा पहुंचे थे। यह फेरबदल टीम इंडिया को खासा भारी पड़ा था और पूरी टीम महज 76 रन बनाकर ढेर हो गई थी। बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव के कारण बल्लेबाजों को अपने रोल समझने में साफतौर पर दिकक्तों का सामना करना पड़ा है। तेज गेंदबाजों को चटकाने होंगे विकेटः टीम इंडिया को अगर सीरीज में वापसी करनी है, तो तेज गेंदबाजों को अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। परिस्थितियों का इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने अब तक भरपूर फायदा उठाया है। हालांकि, भारतीय गेंदबाज इन कंडिशंस का इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में तेज गेंदबाज इस सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके हैं। तीसरे टी20 में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर भी प्रिंस यादव को छोड़कर बाकी भारतीय गेंदबाज छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे। अर्शदीप इस सीरीज में सिर्फ 3 विकेट ही निकाल सके हैं और उनका इकोनॉमी 9.50 रहा है। वहीं, हर्षित राणा ने 10 की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं।

मिडिल ऑर्डर को लेनी होगी जिम्मेदारीः भारत के लिए टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा ने बढ़िया बल्लेबाजी की है। हालांकि, टीम का मिडिल ऑर्डर इस सीरीज में बुरी तरह से फेल रहा है। कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल बल्ले से कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके हैं। ईशान किशन भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। चौथे टी20 में अगर भारतीय टीम को इंग्लैंड को सीरीज जीतने से रोकना है, तो मध्यक्रम के बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा।

भारत बनाम इंग्लैंड

चौथे टी20 में अक्षर पटेल पूरा करेंगे 'शतक'

नई दिल्ली ,एजेसीं। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाना है। इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही अक्षर पटेल बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। दरअसल, अक्षर ने अब तक भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में कुल 99 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 746 रन बनाने के साथ ही 101 विकेट चटकाए हैं। चौथे टी20 में अगर अक्षर को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो यह उनके करियर का 100वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा। वह भारत की तरफ से इस मुकाम तक पहुंचने वाले महज पांचवें खिलाड़ी बनेंगे। अक्षर महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ेंगे। धोनी ने अपने करियर में भारत की ओर से 99 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। अब तक भारत के लिए सिर्फ 4 ही खिलाड़ी 100 से अधिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल सके हैं। रोहित शर्मा (161 मैच) इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं, जबकि हार्दिक पांड्या (138 मैच) दूसरे नंबर पर काबिज हैं। विराट कोहली (127 मैच) तीसरे नंबर पर हैं, तो सूर्यकुमार यादव (115 मैच) के साथ चौथे स्थान पर मौजूद हैं। अक्षर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 100 विकेट पूरे किए थे। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले भारत के पहले स्पिनर बने थे। उन्होंने हैरी ब्रूक को आउट करने के साथ ही यह मुकाम हासिल किया था। हालांकि, अक्षर इस सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। 3 मुकाबलों में अक्षर सिर्फ 15 रन ही बना सके हैं। वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने महज 2 विकेट निकाले हैं। चौथे टी20 में अक्षर से बेहतर प्रदर्शन की आस होगी।

नोस्कोवा ने पहली बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई

कोस्तयुक से होगी भिड़ंत

लंदन,एजेसीं। विंबलडन 2026 में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने बुधवार को एलिस मर्टेंस के खिलाफ 6-3, 7-5 से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जो उनका पहला ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल होगा, जहां उनके सामने यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक से होंगी। लंदन के ऑल-इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब के कोर्ट नंबर 1 पर महज 21 साल उम्र के बावजूद नोस्कोवा ने बड़े मैच में परिपक्वता दिखाई। चेक गणराज्य की 9वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने प्रत्येक सेट में बेल्जियम खिलाड़ी की सर्विस एक-एक बार तोड़ी। नोस्कोवा पिछले साल विंबलडन के चौथे दौर तक पहुंची थीं। वह साल 2018 में येलेना ओस्टापेंको के बाद ऑल-इंग्लैंड क्लब में सबसे कम उम्र की सेमीफाइनलिस्ट बनी हैं। इससे पहले, कोस्त्युक ने बुधवार को सेंटर कोर्ट पर इटली की जैस्मीन पाओलिनी को 6-3, 6-2 से शिकस्त देकर पहली बार विंबलडन सेमीफाइनल और लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई। 12वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने पिछले साल की उपविजेता को 1 घंटा और 9 मिनट में मात दी। पहली बार सेंटर कोर्ट पर खेलते हुए कोस्त्युक ने आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने 19 विनर्स लगाए, जिनमें कई शानदार रिटर्न विनर्स शामिल थे और पाओलिनी को लगातार दबाव में रखा। पाओलिनी को शुरुआती सेट में संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने 15 अनफोर्स्ड एरर किए।

वेस्टइंडीज पर धीमी ओवर-रेट के लिए 10 प्रतिशत जुर्माना लगा, डब्ल्यूटीसी के 2 अंक काटे गए

एंटीगुआ,एजेसीं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम पर श्रीलंका के खिलाफ एंटीगुआ में खेले गए दूसरे टेस्ट के दौरान धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के कारण आईसीसी ने कार्रवाई करते हुए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही टीम के दो महत्वपूर्ण आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंक भी काट लिए गए हैं। आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने यह फैसला तब सुनाया, जब समय की स्वीकृत छूट को ध्यान में रखने के बाद भी वेस्टइंडीज निर्धारित लक्ष्य से दो ओवर पीछे रह गई। आईसीसी के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए लागू आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, 'यदि कोई टीम तय समय के भीतर अपने पूरे ओवर नहीं फेंक पाती है तो प्रत्येक कम ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। इस नियम के तहत अधिकतम जुर्माना मैच फीस का 50 प्रतिशत तक हो सकता है। चूंकि वेस्टइंडीज दो ओवर कम रही, इसलिए टीम पर कुल 10 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया। ' इसके अलावा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्लेइंग कंडीशंस के अनुच्छेद 16.11.2 के तहत प्रत्येक कम ओवर के लिए एक डब्ल्यूटीसी अंक काटा जाता है। इसी नियम के तहत वेस्टइंडीज के खाते से दो अंक घटा दिए गए। अंक कटने के बाद टीम की प्रतिशत अंक (पीसीटी) 15 रह गई है। वेस्टइंडीज मौजूदा डब्ल्यूटीसी तालिका में आठवें स्थान है।

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार कर लिए और प्रस्तावित सजा को मान लिया, जिसके चलते औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह आरोप मैदानी अंपायर पॉल रीफेल और अहसान रजा, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद तथा चौथे अंपायर डेइटन बटलर ने लगाए थे।

मैच की बात करें तो एंटीगुआ में खेला गया दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा। वेस्टइंडीज ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ 23 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है।

बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम घोषित

मिल्टन शुम्बा और न्यूमैन न्यामहुरी को मौका

हरारे,एजेसीं। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 3 टी20 मैचों की घरेलू सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट ने बुधवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। टीम की कमान सिकंदर रजा के हाथ में है। इस टीम में ज्यादातर वही खिलाड़ी हैं जो टी20 विश्व कप 2026 में जिम्बाब्वे को सुपर-8 तक पहुंचाने वाले कैंपेन का हिस्सा रहे थे। हरारे में चल रही वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद 15, 17 और 19 जुलाई को बुलावायो में 3 टी20 मैच खेले जाने हैं। टीम में दो बदलाव हुए हैं। युवा तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी और बल्लेबाज मिल्टन शुम्बा को शामिल किया गया है। न्यामहुरी ने टी20 फॉर्मेट में अभी तक डेब्यू नहीं किया है। शुम्बा ऑस्ट्रेलिया में 2022 टी20 विश्व कप के बाद पहली बार टी20 टीम में लौटे हैं। बल्लेबाज बेन कुरेन, जिन्हें इस साल की शुरुआत में ब्रेंडन टेलर की चोट के बाद टी20 विश्व कप टीम में शामिल किया गया था, ने अपनी जगह बरकरार रखी है। ग्रेम क्रेमर बाएं हाथ में इंजरी की वजह से चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

चयनकर्ता संयोजक डेविड मुटेंडेरा ने कहा कि टीम का चयन करते समय निरंतरता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था।

उन्होंने कहा, 'टी20 विश्व कप ने दिखाया कि यह ग्रुप क्या करने में काबिल है, इसलिए निरंतरता हमारे लिए एक जरूरी बात थी। हम सुपर आठ तक पहुंचने वाली टीम के कोर को एक साथ रखना चाहते थे, साथ ही उन खिलाड़ियों के लिए भी जगह बनाना चाहते थे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से अपने लिए मौके बनाए हैं। यह सीरीज टीम को आगे बढ़ने का एक और मौका देती है क्योंकि हम आगे के बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। ' जिम्बाब्वे टीमः सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजराबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा।

शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : कमिश्नर

मैहर जिले की समीक्षा बैठक सम्पन्न

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने गुरुवार को मैहर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं विकास कार्यों एवं विभागीय उपलब्धियों का गहन समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो बैठक में कलेक्टर मैहर मती बिदिशा मुखर्जी पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, अपर कलेक्टर संजना जैन, सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम एसपी मिश्रा, डॉ. आरती सिंह, डिप्टी कलेक्टर आशिमा पटेल, सीएमएचओ डॉ. मनोज शुक्ला, उप संचालक सामाजिक न्याय राजीव सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र बांगरे, आरटीओ रवि बेरेलिया

सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करें तथा आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाएं लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से योजनाओं की सतत समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए उन्होंने आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थानों पर पौधारोपण एवं उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए साथ ही एक बगिया मां के नाम अभियान के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों को राशि जारी हो चुकी है उनके आवासों का निर्माण शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाए अपूर्ण कार्यों में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए उन्होंने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए इनके शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के निर्देश दिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बंद पड़े शौचालयों का सत्यापन कर उन्हें पुनः उपयोग में लाने पर भी जोर दिया कमिश्नर ने विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छता पेयजल व्यवस्था एवं गुणवत्तापूर्ण पोषण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए कमिश्नर ने सीईओ जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी, डीपीएम एनआरएलएम को स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार तेल, मसालों का उपयोग स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में शत-प्रतिशत करें स्वच्छ भारत मिशन के कार्यो की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने डीईओ, डीपीसी को निर्देशित किया कि जिले के शत-प्रतिशत विद्यालयों में शौचालयों की साफ-सफाई का कार्य स्वच्छता साथी के माध्यम से कराये कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन, कुपोषित बच्चों का एनआरसी में उपचार, सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग तथा आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

बंदूक के साथ निरीक्षण पड़ा भारी, उपयंत्री सतीश समेले निलंबित

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। शासकीय निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान लाइसेंसी बंदूक साथ ले जाना जनपद पंचायत मझगवां में पदस्थ उपयंत्री सतीश समेले को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है जानकारी के अनुसार उपयंत्री सतीश समेले ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे इस दौरान उनके पास निजी लाइसेंसी बंदूक मौजूद थी। निरीक्षण से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया। कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ द्वारा मामले की जांच कराई गई जांच के दौरान उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपने जवाब में उन्होंने बंदूक साथ ले जाने की बात स्वीकार करते हुए इसे सुरक्षा कारणों से आवश्यक बताया, लेकिन विभाग ने उनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह ने निलंबन आदेश जारी करते हुए प्रथम दृष्टया इसे शासकीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन और अनुशासनहीनता माना है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सतना निर्धारित किया गया है प्रशासन ने मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी है जांच में वित्तीय अनियमितताओं और अन्य शिकायतों की भी पड़ताल की जाएगी अधिकारियों का कहना है कि शासकीय कार्यों में अनुशासन और नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है।

निलंबित उपयंत्री का दावा- जनपद से भोपाल तक चलता है कमीशन सिस्टम, हाईकोर्ट में पेश करूंगा सबूत

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मझगवां जनपद पंचायत के निलंबित संविदा उपयंत्री सतीश समेले ने गुरुवार को मीडिया के सामने विभाग में कथित कमीशनखोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने दावा किया कि जनपद स्तर से लेकर भोपाल तक निर्माण कार्यों में कमीशन का एक व्यवस्थित तंत्र संचालित होता है समेले का कहना है कि उनके पास इससे जुड़े ऑडियो वीडियो और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य हैं जिन्हें वह हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेंगे समेले ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में अलग-अलग स्तर पर कमीशन तय रहता है उन्होंने दावा किया कि सरपंच, सचिव, जीआरएस, उपयंत्री, सहायक यंत्री और जनपद स्तर के अधिकारियों तक निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से राशि ली

जाती है उनका यह भी आरोप है कि निरीक्षण के लिए आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों तक भी कथित रूप से धन पहुंचाया जाता है उन्होंने कहा कि उपयंत्री अब तकनीकी कार्यों से अधिक वसूली का माध्यम बन गए हैं। उनके अनुसार वे स्वयं भी इस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं और उनसे भी कथित रूप से वसूली कराई गई समेले ने अपने ऊपर लगे कमीशन लेने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरे तंत्र को छिपाने का प्रयास ह उल्लेखनीय है कि सतीश समेले को निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर जाने और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों के बाद पहले कार्यालय से संबद्ध (ऑफिस अटैच) किया गया था। बाद में विभागीय जांच के दौरान उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन पर शांतिधाम निर्माण, सामग्री भुगतान, कथित कमीशन मांगने तथा अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने सहित कई आरोप लगाए गए हैं समेले ने कहा कि वह अपने सभी दावों के समर्थन में न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे समाचार लिखे जाने तक उनके आरोपों पर संबंधित विभाग या वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

PMGSY जीएम उमेश साहू पर भ्रष्टाचार के आरोप, ठेकेदारों ने मंत्री प्रतिमा बागरी से की कार्रवाई की मांग

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) सतना के महाप्रबंधक उमेश कुमार साहू के खिलाफ ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतों का निराकरण नहीं होने से नाराज संविदाकार पिछले चार दिनों से पीएमजीएसवाई कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। ठेकेदारों ने मामले की शिकायत नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है दर्शन कर रहे ठेकेदारों का आरोप है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों के भुगतान में अनियमितताएं की जा रही हैं उनका कहना है कि कई कार्यों के अंतिम भुगतान में नियमों के विपरीत कटौती की गई है तथा परफॉर्मेंस गारंटी की राशि भी लंबे समय से रोकी गई है ठेकेदारों का दावा है कि भुगतान प्रक्रिया में देरी और विभागीय स्तर पर लिए जा रहे निर्णयों से निर्माण एजेंसियां आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार

विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक समाधान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया। उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल भुगतान से जुड़ा नहीं है, बल्कि पारदर्शी व्यवस्था और नियमों के पालन की मांग को लेकर है पीड़ित संविदाकारों ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को सौंपे ज्ञापन में पीएमजीएसवाई के कार्यों, भुगतान प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है उन्होंने आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है ठेकेदारों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा वहीं इस मामले में संबंधित विभाग या पीएमजीएसवाई अधिकारियों की ओर से आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है मामला अब मंत्री स्तर तक पहुंचने के बाद ठेकेदारों को कार्रवाई की उम्मीद है। विभागीय जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पीएमजीएसवाई में भुगतान को लेकर विवाद गहराया, तीसरे दिन भी धरने पर बैठे संविदाकार

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्मित सड़कों के भुगतान में कथित अनियमितताओं और परफॉर्मेंस गारंटी की राशि रोके जाने के विरोध में संविदाकारों का धरना गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। पीएमजीएसवाई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों ने भुगतान में मनमानी कटौती का आरोप लगाते हुए लंबित राशि जारी करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की धरने का नेतृत्व कर रहे संविदाकारअनिल सिंहने आरोप लगाया कि हाल ही में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरीद्वारा शिलान्यास की गई दो सड़कों के अंतिम भुगतान में नियमों के विपरीत 14.64 लाख रुपये की कटौती की गई है साथ ही दोनों परियोजनाओं की 22.91 लाख रुपये की परफॉर्मेंस गारंटी भी अब तक जारी नहीं की गई है संविदाकारों के अनुसार, सतना-पन्ना मार्ग से बचवई तथा सतना-पन्ना मार्ग से छींदा तक निर्मित सड़कों के अंतिम भुगतान में प्राइस एस्केलेशन के नाम पर कटौती की गई। उनका आरोप है कि भौतिक सत्यापन पूरा होने के बावजूद पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया और माप पुस्तिका में भी मनमाने संशोधन किए गए। उन्होंने दावा किया कि जिले में करीब 20 ठेकेदारों के 15 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान विभिन्न कारणों से लंबित हैं बुधवार शाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह और एसडीएम राहुल सिलाडिया धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान संविदाकारों ने ज्ञापन सौंपकर पीएमजीएसवाई के महाप्रबंधक को हटाने, उनके कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने की मांग की जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि संविदाकारों की शिकायतों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर एमपीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेज दी गई है। शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संविदाकारों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

जन्मदिन पर समाजसेवी विनोद गेलानी ने किया 70वां रक्तदान, युवाओं को दिया सेवा का संदेश

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जन्मदिन को मानव सेवा का पर्व बनाते हुए समाजसेवी एवं रक्तदान प्रेरक विनोद गेलानी ने अपने जन्मदिन पर 70वां स्वैच्छिक रक्तदान कर समाज के सामने प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया इस अवसर पर उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की विनोद गेलानी पिछले 35 वर्षों से स्वैच्छिक रक्तदान अभियान से जुड़े हुए हैं और जरूरतमंद मरीजों तक समय पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके प्रयासों से अब तक 7,150 यूनिट से अधिक रक्तदान कराया जा चुका है, जो जिले में रक्तदान जागरूकता की दिशा में उल्लेखनीय

उपलब्धि मानी जाती है रक्तदान के बाद उन्होंने कहा कि जन्मदिन मनाने का सबसे अच्छा तरीका किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का प्रयास करना है उनका कहना था कि एक यूनिट रक्त कई मरीजों के उपचार में उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए उन्होंने विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के स्वस्थ नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ और अन्य विशेष अवसरों को रक्तदान जैसे सेवा कार्यों से जोड़कर समाज में मानवीय संवेदनाओं का संदेश दें कार्यक्रम में उपस्थित शुभचिंतकों और समाजसेवियों ने विनोद गेलानी के 70वें रक्तदान की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ जरूरतमंद मरीजों के जीवन की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस अवसर पर प्रह्लाद ज्ञानचंद हासवानी, गंगाराम सचदेव, महेश रावलानी, बसंत खत्री, कन्हैयालाल कामदार, किशोर वलेचा, आशीष मोगिया, रंजीत सेनानी, जयंत हासवानी, मनीष सदानी, अमित घोघवानी, सागर जसवानी, ब्लड बैंक के मिर्जा जी सहित अनेक समाजसेवी एवं शुभचिंतक उपस्थित रहे।

सतना में शुरू हुआ जबलपुर रीजन का पहला एन-जेन पोस्ट ऑफिस, युवाओं को मिलेगा वर्क कैफे जैसा आधुनिक अनुभव

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। डाक सेवाओं को आधुनिक तकनीक और नई पीढ़ी की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में इंडिया पोस्ट ने सतना जिले को बड़ी सौगात दी है गुरुवार को मेडिकल कॉलेज परिसर में जिले के पहले जेन-जी थीम आधारित नेक्स्ट जनरेशन (एन-जेन) पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल विनीत माथुर ने इसका उद्घाटन किया यह जबलपुर रीजन का अपनी तरह का पहला पोस्ट ऑफिस है, जिसे पारंपरिक डाकघरों से अलग आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं के साथ विकसित किया गया है एन-जेन पोस्ट ऑफिस का डिजाइन युवाओं को ध्यान में

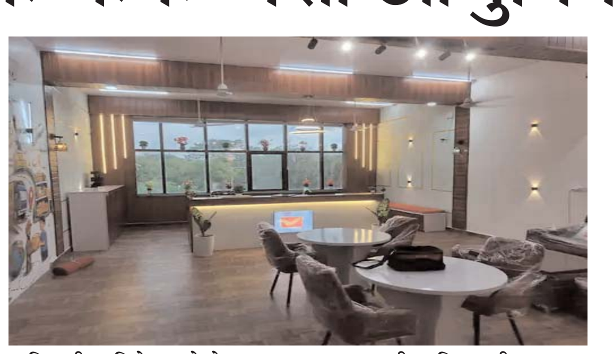

रखकर तैयार किया गया है। इसका इंटीरियर आधुनिक वर्क कैफे की तर्ज पर विकसित किया गया है ताकि यहां आने वाले विद्यार्थी युवा और अन्य ग्राहक डाक सेवाओं का उपयोग करने के साथ-साथ अध्ययन, कार्य और संवाद के लिए भी आरामदायक वातावरण प्राप्त कर सकें परिसर में निःशुल्क वाई-फाई आरामदायक बैठने की व्यवस्था लैपटॉप एवं मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, कॉफी वेंडिंग मशीन तथा पुस्तकों और बोर्ड गेम्स से सुसज्जित बुक-बूथ जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं इससे पोस्ट ऑफिस केवल डाक सेवाओं का केंद्र ही नहीं बल्कि सीखने और काम करने के लिए भी उपयोगी स्थान बन गया है मुख्य डाकघर के जनसंपर्क अधिकारी अभिषेक खरे ने बताया कि एन-जेन पोस्ट ऑफिस को 'डू-इट-योरसेल्फ' (डीआईवाई) अवधारणा पर विकसित किया गया है इसके तहत ग्राहक बिना किसी कर्मचारी की सहायता के सेल्फ-बुकिंग कियोस्क के माध्यम से स्वयं ही पार्सल और डाक बुक कर सकेंगे इसके साथ ही क्यूआर कोड आधारित तत्काल डिजिटल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है जिससे पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, सरल और पारदर्शी होगी इस पोस्ट ऑफिस की एक विशेष सुविधा माय स्टाम्प काउंटर भी है यहां ग्राहक अपनी पसंद की तस्वीर डिजाइन संस्थान के लोगो या किसी विशेष अवसर की थीम के साथ व्यक्तिगत डाक टिकट तैयार और प्रिंट करा सकेंगे यह सुविधा स्मृति-चिह्न उपहार और विशेष आयोजनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगी इंडिया पोस्ट के अधिकारियों का कहना है कि एन-जेन पोस्ट ऑफिस का उद्देश्य पारंपरिक डाक सेवाओं को डिजिटल तकनीक के साथ जोड़कर अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है इस पहल से युवाओं को आधुनिक और सुविधाजनक डाक सेवाओं से जोड़ने के साथ-साथ इंडिया पोस्ट की सेवाओं को भी नई पहचान मिलेगी अधिकारियों के अनुसार सतना में शुरू किया गया यह मॉडल भविष्य में प्रदेश के अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है जिससे डाक सेवाओं का स्वरूप और अधिक आधुनिक तथा तकनीक आधारित बन सके।

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिला कार्यकारिणी घोषित, सभी प्रमुख वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिला सतना की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है कार्यकारिणी का गठन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति तथा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार, संभागीय संगठन प्रभारी विजय दुबे, जिला संगठन प्रभारी जीएस ठाकुरएवं भाजपा जिलाध्यक्ष पं. भगवती प्रसाद पांडे की अनुशंसा पर किया गया पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष राबेन्द्र सिंह ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि संगठन को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाने के उद्देश्य से अनुभवी एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई टीम संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जिला मीडिया प्रभारी अतुल सिंह परिहार ने बताया कि नई कार्यकारिणी के गठन में संगठनात्मक अनुभव के साथ सामाजिक संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कार्यकारिणी में पिछड़ा वर्ग की विभिन्न प्रमुख जातियों एवं जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है ताकि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके उन्होंने बताया कि नवगठित टीम पार्टी की रीति-नीति को गांव-गांव तक पहुंचाने, संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाएगी। पार्टी पदाधिकारियों ने नव-नियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन हित में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादो का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।